छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

RNI Reg. No.-CHHHIN/2009/36148
डाक पंजीयन क्र.-45/Surguja Dn/2024-26

वर्ष - 17 ■ अंक - 12 ■ अम्बिकापुर, मंगलवार 30 दिसम्बर 2025 पृष्ठ -8 ■ मूल्य - 1 रूपये

WWW.cgfrontline.com

व्यवसायी पर जानलेवा हमला करके 20 लाख नकद लूटने वाले पुलिस को देखकर खेत में लगाने लगे दौड़

घेराबंदी करके देर रात पुलिस दो आरोपियों को गिरफ्तार की, लूटी गई रकम और मोटरसायकल बरामद

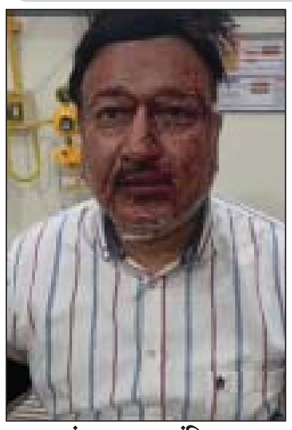

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। कोतवाली थाना क्षेत्र के सत्तीपारा कैलाश मोड़ के पास रविवार की रात व्यवसायी पर जानलेवा हमला करके 20 लाख रुपये लूटने के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने घेराबंदी करके चंद घंटे में दो आरोपियों को गिरफ्तार करके इनसे शत-प्रतिशत लूट की रकम, व्यवसायी का मोबाइल फोन और एक मोटरसायकल बरामद कर लिया है। आरोपियों में एक व्यवसायी के यहां पूर्व में काम करने वाला एक कर्मचारी शामिल था, जिसे उन्होंने काम से निकाल दिया था। ऐसे में बदले की भावना से उक्त कर्मचारी के द्वारा वारदात को अंजाम देने की संभावना बलवती हो रही है। पुलिस को आरोपियों को गिरफ्तार करने देर रात खेत में दौड़ लगानी पड़ी।

जानकारी के मुताबिक रानी सती मंदिर कॉलोनी निवासी व्यवसायी अनिल अग्रवाल का शहर के श्री राम मंदिर रोड में मोबाइल का थोक कारोबार है, वे हिंदुस्तान लीवर के फ्रेंचाइजी धारक भी हैं। अग्रवाल इंटरप्राइजेज इन्द्रपस्थ के संचालक अनिल अग्रवाल रविवार की रात को रोजाना की तरह दुकान बंद करके दिन भर की बिक्री की रकम लगभग 20 लाख रुपये और तीन मोबाइल फोन बैग में रखकर स्कूटी से अपने घर लौट रहे थे। सत्तीपारा में कैलाश मोड़ के पास अंधेरे में दीवार के पीछे घात लगाकर बैठे किसी व्यक्ति ने अचानक उन पर बांस के डंडे से हमला कर दिया, जिससे खून निकलने लगा और वे बुरी तरह से लहूलुहान हो गए। घटना में अनिल अग्रवाल स्कूटी सहित सड़क पर गिर गए, वे शोर मचा पाते, इसके पहले बदमाश उनके हाथ से रुपये से भरा बैग छीनकर अंधेरे में फरार हो गए। शहर के सज्जन कॉलोनी निवासी अंकित गोयल पिता सज्जन गोयल ने घटना की जानकारी थाना कोतवाली में दी थी, जिस पर पुलिस ने थाना कोतवाली में बीएनएस की धारा 109(1), 311, 309(6), 3(5) पंजीबद्ध किया था और आहत का डॉक्टरी मुलाहिजा कराया था।

इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा राजेश अग्रवाल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह ढिल्लो एवं नगर पुलिस अधीक्षक राहुल बंसल के मार्गदर्शन में थाना अंबिकापुर, मणिपुर, गांधीनगर एवं यातायात पुलिस को कंट्रोल रूम के माध्यम से निर्देश देकर शहर के सभी प्रमुख निकास मार्गों पर कड़ी नाकाबंदी करके वाहनों की सघन चेकिंग एवं पूछताछ की जाने लगी। साइबर सेल की टीम को घटनास्थल रवाना किया गया। टीम ने सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से अवलोकन किया। प्राप्त सीसीटीव्ही फुटेज, पूछताछ के बीच मुखबिर से पुलिस को पता चला कि कुछ संदिग्ध जगदीशपुर के खेतों में छिपे हुए हैं। पुलिस टीम खेत में संदिग्धों को पकड़ने के लिए घेराबंदी की तो दो संदिग्ध भागने लगे। इस दौरान संदिग्धों के पास मौजूद पैसे से भरा बैग गिर गया एवं कुछ ही दूरी पर खड़ी सफेद रंग की पल्सर एनएस मोटरसाइकिल को छोड़कर आरोपी वहां से भाग गए। पुलिस ने पल्सर मोटरसाइकल एवं नकदी रकम 18 लाख रुपये जप्त कर लिया। फरार दोनों आरोपियों की पतासाजी में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शशिकांत सिन्हा एवं साइबर सेल प्रभारी सहायक उप निरीक्षक अजीत मिश्रा की टीम ने आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश दी। इस दौरान तकनीकी माध्यमों से पता चला कि आरोपी जगदीशपुर के आस-पास ही खेत में छिपे हैं। आसपास के इलाके को पूरी तरह से घेराबंदी करके पुलिस टीम ने इन्हें हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार किया।

कैट करेगा पुलिस टीम का सम्मान

व्यवसायी अनिल अग्रवाल पर हमला और लूट की घटना में शामिल अपराधियों तक पहुंचने और लूट की रकम और आरोपियों की मोटरसायकल को बरामद करने में मिली सफलता की सराहना व्यापारियों के संगठन, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने की है। कैट ने साइबर सेल एवं पूरी पुलिस टीम को तत्परतापूर्वक कार्रवाई के लिए सम्मानित करने का निर्णय लिया है। कैट ने जारी बयान में कहा है कि इस सफल कार्रवाई से आम जनता एवं व्यापारियों के बीच पुलिस के प्रति विश्वास और अधिक सुदृढ़ हुआ है। सरगुजा पुलिस के द्वारा घटना को गंभीरता से लेकर जिस प्रकार प्रभावी कार्रवाई की गई, इससे क्षेत्रवासी स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कैट ने सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक दीपक झा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल एवं पूरी पुलिस टीम को इस सफलता के लिए बधाई प्रेषित की है।

पुलिस इन्हें की गिरफ्तार

आरोपी दीपक दास पिता जयमंगल दास 24 वर्ष खालपरा अमगासी लखनपुर का वहीं रोहित दास पिता भकुस दास भातुपारा अंबिकापुर के कब्ज़े से पुलिस ने लूट की शेष रकम दो लाख रुपये नकद बरामद करने सफलता हासिल की है। आरोपियों के विरुद्ध विधिवत कार्रवाई करते हुए इन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

कार्रवाई में ये रहे शामिल

कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शशिकांत सिन्हा, प्रदीप जायसवाल, उप निरीक्षक सीपी तिवारी, सहायक उप निरीक्षक अदीप सिंह, विवेक पांडेय, अजीत कुमार मिश्रा, प्रधान आरक्षक भोजराज पासवान, विकास सिन्हा, अजय पांडेय, छत्रपाल सिंह, जयदीप सिंह, आरक्षक मनीष सिंह, विवेक राय, नितिन सिन्हा, देवेंद्र पाठक की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

व्यवसायी से लगभग 20 लाख रुपये की लूट के मामले में शामिल दो आरोपियों को नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में साइबर थाना और कोतवाली थाना की पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से लूटी गई रकम और तीन मोबाइल फोन की शत-प्रतिशत बरामदगी हो गई है। मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की गई है।

अमोलक सिंह ढिल्लो
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सरगुजा

कुलपति प्रो. लाकपाले को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। प्रोफेसर राजेंद्र लाकपाले, कुलपति संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शैक्षणिक उत्कृष्टता, नवाचार नेतृत्व, उच्च शिक्षा और सामुदायिक उन्नति में परिवर्तनकारी योगदान में आजीवन समर्पण हेतु 'लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड' से सम्मानित किया गया। यह सम्मान कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, रायचूर के सहयोग से राष्ट्रीय कृषि विकास सहकारी लिमिटेड (एनएडीसीएल) द्वारा 29-31 दिसंबर 2025 कों आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी 'कृषि, पशु चिकित्सा और संबद्ध विज्ञान में सतत नवाचार' में प्रदान किया गया। यह पुरस्कार विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही गर्व एवं गौरव का अवसर है।

विवि की इनोवा कार खाई में गिरी, बिना अनुमति लेकर गया था चालक, एक की मौत

घायल चालक ने कहा-पता नहीं कैसे हुई दुर्घटना, होश आया तो था अस्पताल में

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय की शासकीय इनोवा कार बनारस रोड में लटोरी पुलिस चौकी अंतर्गत अनियंत्रित होकर पलट गई, हादसे में इनोवा चालक सहित दो घायल हुए थे, एक की मौत हो गई। विश्वविद्यालय में बस चलाने वाला चालक प्रबंधन को जानकारी दिए बगैर शासकीय वाहन लेकर गैस भराने गया था और नशे में लापरवाही पूर्वक वाहन चला रहा था। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त शासकीय वाहन को अपने कब्जे में ले लिया है। विश्वविद्यालय प्रबंधन शासकीय वाहन को निजी काम के लिए चालक द्वारा ले जाने के बाद भी बेफिक्र रहा। एक्सीडेंट की सूचना मिलने पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे, और घायल चालक की स्थिति का जायजा लिया।

जानकारी के मुताबिक मृतक रमेश विश्वकर्मा पिता सतासी विश्वकर्मा 38 वर्ष, ग्राम अतायर, जिला गोरखपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, जो वर्तमान में सुभाषनगर अंबिकापुर में अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहता था। बगल में रविन्द्र सिंह रहता है, जो संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय में बस का चालक है। 28 दिसम्बर को सुबह करीब 10 बजे रविन्द्र घर के बगल में रहने वाले रमेश विश्वकर्मा को शासकीय वाहन में लेकर गैस भरवाने के लिए मेंड्रा गया था, और 10 मिनट बाद गैस भराकर घर वापस आ गया। इसके बाद वह रमेश को मंडी से सस्ता सब्जी लेकर आने की बात कहते हुए साथ चलने के लिए कहा, लेकिन वह जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, जिस पर रविन्द्र जबरन उसको अपने साथ इनोवा वाहन क्रमांक सीजी 02-5504 में बैठाकर साथ ले गया, इसके बाद दोनों शराब पिए थे। रमेश अपना मोबाइल फोन घर में ही छोड़ दिया था। दोपहर करीब 2.30 बजे तक जब दोनों वापस घर नहीं लौटे तो रमेश की पत्नी नीलम देवी ने रविन्द्र के मोबाइल में फोन करके कहीं जाने की बात कहते हुए पति को घर छोड़ देने के लिए कहा, तो 10 मिनट में पहुंच रहे हैं, कहकर वह फोन काट दिया।

आधे घंटे तक जब दोनों वापस नहीं आए तो रविन्द्र सिंह की पत्नी सीमा अपने पति के मोबाइल में कॉल की, तो फोन कोई दूसरा व्यक्ति रिसीव किया और बताया कि फोन धारक का सूरजपुर जिला के लटोरी पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम मजीरा में छतरपुर चौक के पास एक्सीडेंट हो गया है। गाड़ी में दो लोग थे, एक आदमी को काफी चोंट लगा है। इसकी सूचना मिलने पर जब रमेश की पत्नी घटनास्थल पर गई तो सड़क के किनारे खाई में कार क्षतिग्रस्त हालत में पड़ी थी और रमेश विश्वकर्मा पीठ के बल अचेत हालत में गाड़ी से थोड़ी दूर पड़ा था, उसके सिर, चेहरे में चोट लगा था, जिससे काफी खून का रिसाव हुआ था। दाहिना पैर घुटना पास से टूटा हुआ नजर आ रहा था। गांव के लोगों ने बताया कि ड्रायवर को इलाज के लिए अस्पताल ले गए हैं। कुछ देर बाद पुलिस व दुर्घटनाग्रस्त इनोवा वाहन चालक के परिवार वाले आए और रमेश को निजी वाहन से लटोरी शासकीय अस्पताल लेकर गए, यहां से प्राथमिक इलाज के बाद रिफर करने पर रमेश को लेकर स्वजन होलीक्रॉस अस्पताल अंबिकापुर लेकर पहुंचे, यहां आपातकालीन वार्ड में जांच के बाद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन के सुपुर्द कर दिया है।

बिना अनुमति के लेकर गया वाहन

शासकीय वाहन को जमा करने के बजाय चालक बिना अनुमति के कैसे लेकर गया, इसकी जांच के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। चालक रविन्द्र गाड़ी रखने जा रहा हूं कहा था, इसके बाद एक्सीडेंट की सूचना मिली। शराब पीकर शासकीय वाहन चलाना प्रथम दृष्टया अपराध है।

एस.पी. त्रिपाठी,
कुलसचिव
संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा

प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से कलेक्टर जनदर्शन

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। जिले में प्रत्येक सप्ताह के सोमवार को आयोजित होने वाला कलेक्टर जनदर्शन अब प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार को प्रात: 11 बजे से जिला कलेक्टरेट कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित किया जाएगा। कलेक्टर अजीत वसंत ने जनदर्शन कार्यक्रम में शहरी, ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले आमजनों, ग्रामीणों को किसी प्रकार से कोई परेशानी न हो, इसके लिए समस्त जिला स्तरीय अधिकारी एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों को उक्त व्यवस्था का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिए हैं।

नारियल भूसी के आड़ में गांजा की तस्करी, 6 करोड़ के गांजा के साथ तीन अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार

1198.460 किलो गांजा बरामद, उड़ीसा से राजस्थान ले जाते बसंतपुर थाना पुलिस ने पकड़ा

छ.ग.फ्रंटलाइन बलरामपुर। अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बसंतपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने उड़ीसा से राजस्थान ले जाए जा रहे लगभग 6 करोड़ रुपये का 1198.460 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद कर तीन अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करी में प्रयुक्त टाटा ट्रक वाहन को भी जप्त किया गया है। गांजा को नारियल की भूसी के भीतर छिपाकर ट्रक में ले जाया जा रहा था।

बता दें कि पुलिस अधीक्षक बलरामपुर ने जिले के सभी थाना-चौकी प्रभारियों को मादक पदार्थों के अवैध परिवहन पर सख्ती से रोक लगाने के आदेश दिए हैं। इसी क्रम में 28 दिसंबर की दरम्यानी रात थाना प्रभारी बसंतपुर निरीक्षक जितेन्द्र सोनी को मुखबिर से सूचना मिली कि धनवार बॉर्डर पर एक टाटा ट्रक क्रमांक आरजे 32 जीई 0960 में नारियल की भूसी के अंदर गांजा छिपाकर ले जाया जा रहा है। सूचना पर पुलिस टीम गवाहों के साथ मौके पर पहुंची और ट्रक को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान ट्रक के डाले में भूरे रंग के टेप से लिपटे 40 पैकेटों में भरा कुल 1198.460 किलोग्राम गांजा मिला, जिसकी अनुमानित कीमत 5 करोड़ 99 लाख रुपये बताई जा रही है। तस्करी में प्रयुक्त ट्रक वाहन को भी पुलिस ने जप्त कर लिया है।

इन आरोपियों को जेल भेजी पुलिस

पुलिस ने आरोपी अमरीश कुमार पिता संतलाल 23 वर्ष, निवासी पुरे पहलवान समरौता, थाना महाराजगंज, जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश, अम्बरीश कुमार पटेल पिता जगदेव प्रसाद पटेल 33 वर्ष, निवासी शाह मोहम्मद पूर्व अप्या, थाना नगराम, मोहनलालगंज, लखनऊ उत्तर प्रदेश व मनीष कुमार पिता रामभवन 20 वर्ष, निवासी मैनझर, थाना शिवरतनगंज, जिला अमेठी उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों के विरुद्ध थाना बसंतपुर में बीएनएस की धारा 20(बी)(2)(सी) एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

परसोढीकला में एसईसीएल प्रबंधन ने शुरू किया कोयला उत्पादन

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। एसईसीएल बिश्रामपुर क्षेत्र के इतिहास में आज का दिन स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो गया, जब अमेरा ओपन कास्ट माइंस अंतर्गत परसोढीकला ग्राम पंचायत की अधिग्रहित भूमि से विधिवत कोयला उत्पादन का शुभारंभ किया गया। वर्षों की प्रतीक्षा, संघर्ष, संवाद और समझौते के बाद शुरू हुई यह परियोजना न केवल बिश्रामपुर क्षेत्र बल्कि पूरे एसईसीएल और कोल इंडिया के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में देखी जा रही है। गौरतलब है कि अमेरा ओपन कास्ट माइंस के विस्तार को लेकर शुरुआती दौर में हालात बेहद तनावपूर्ण रहे। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, मुआवजा और आजीविका के सवालों पर ग्रामीणों में असंतोष उभर आया था। कई बार स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस और ग्रामीणों के बीच तीखी झड़पें भी हुईं, जिससे पूरा क्षेत्र सुर्खियों में आ गया। उस दौर में यह आशंका जताई जाने लगी थी कि परियोजना लंबे समय तक ठप रह सकती है, लेकिन एसईसीएल प्रबंधन ने पीछे हटने के बजाय संवाद का रास्ता

चुना। लगातार बैठकों और व्यक्तिगत चर्चाओं के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याओं को सुना गया। मुआवजा, पुनर्वास और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर सहमति बनाकर विश्वास बहाली की कोशिश की गई। यही कारण रहा कि जिस परियोजना को लेकर कभी विरोध चरम पर था, आज उसी धरती से विकास की नई कहानी शुरू हो सकी। ज्ञात हो कि आज जैसे ही परसोढीकला की अधिग्रहित भूमि पर खदान से कोयला निकला तब उत्साह का माहौल देखने को मिला। परियोजना के चालू होने से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही परिवहन, छोटे व्यवसाय, दुकानें और अन्य सहायक उद्योगों को भी नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है।एसईसीएल अमेरा ओपन कास्ट माइंस से कोयला उत्पादन की शुरुआत को प्रबंधन ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम मान रहा है। इससे न केवल बिश्रामपुर क्षेत्र की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि कोल इंडिया के कुल उत्पादन लक्ष्य को हासिल करने में भी यह माइंस अहम भूमिका निभाएगी। देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में इस परियोजना का योगदान आने वाले वर्षों में और भी महत्वपूर्ण साबित होने की संभावना है। कुल मिलाकर परसोढीकला में शुरू हुआ कोयला उत्पादन केवल एक औद्योगिक गतिविधि नहीं, बल्कि संघर्ष, संवाद और सहयोग से निकली सफलता की मिसाल है। यह परियोजना आने वाले समय में बिश्रामपुर क्षेत्र को आर्थिक मजबूती देने के साथ-साथ देश की ऊर्जा रीढ़ को और सशक्त बनाएगी।

बवाल के बाद कलेक्टर और थाना प्रभारी पर गिरी गाज

ग्रामीणों और राजनेताओं की अड़ंगेबाजी के कारण अमेरा खदान से कोयला उत्पादन का कार्य वर्ष 2018 से पूरी तरह बाधित था, जिससे एसईसीएल प्रबंधन को अब तक कई करोड़ का नुकसान अनुमानित है। प्रबंधन खदान को शुरू कराने कई बार प्रयास कर चुका लेकिन राजनीतिक अड़ंगेबाजी के कारण प्रशासनिक सहयोग नहीं मिलने के कारण खदान से कोयला उत्पादन प्रभावित रहा। सरगुजा के तत्कालीन कलेक्टर विलास भोस्कर के दृढ़ इच्छाशक्ति और पुलिस अमले के सहयोग से आखिरकार प्रबंधन ने खदान शुरू कराने में सफल रही। जिससे आज से यहां कोयला उत्पादन शुरू कर लिया गया है। 3 दिसम्बर को ग्रामीणों एवं प्रशासनिक अमले के बीच हुई संघर्ष की स्थिति व बवाल के बाद कलेक्टर विलास भोस्कर का राज्य सरकार ने तबादला कर दिया, वहीं तत्कालीन लखनपुर थाना प्रभारी मनीष सिंह परिहार को इसी घटना के बाद पीएचक्यू अटैच कर दिया गया है।

युवक के बाइक में रखे बैग समेत 49 हजार ले भागे अज्ञात बाइक सवार

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। एसईसीएल महाप्रबंधक कार्यालय के सामने सोमवार को दोपहर हुई उठाईगिरी की घटना में अज्ञात बाइक सवार युवकों ने युवक का पीछाकर उसके बैग में रखे 49 हजार रुपए नगद सहित जानवरों की दवा, बैंक पासबुक लेकर नौ दो ग्यारह हो गए हैं। युवक की रिपोर्ट पर बिश्रामपुर पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। गौरतलब है कि जयनगर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत राजापुर निवासी अमरनाथ सिंह पिता शिवनाथ जो गांव में ग्रामीण गौ सेवक का कार्य करता है। सोमवार की दोपहर करीब साढ़े 12 बजे अपने एसबीआई बिश्रामपुर बैंक शाखा के बचत खाता से घर में लगे काम में मजदूरों को पैसे देने के उद्देश्य से 49 हजार रुपए बैंक से आहरण कर वह महाप्रबंधक कार्यालय के सामने स्थित शारदा जनरल स्टोर में किराना समान लेने रुका था। वह बाइक खड़ी कर बैग को बाइक में रखकर दुकान से समान ले रहा था। तभी बैंक से ही पीछाकर रहे दो बाइक सवार युवक उसके बाइक में रखे बैग को लेकर फरार हो गए हैं। उठाईगिरी के शिकार हुए युवक ने बताया कि वह दुकान की सीढ़ी चढ़ रहा था, इसी बीच बाइक सवार युवकों ने उसका बैग पार कर दिया है। घटना के बाद दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में दो युवक बैग उठाकर ले जाते दिख रहे हैं, जो बैग लेकर तेजी से बाइक में अंबिकापुर की ओर भाग निकले हैं। सूचना पर बिश्रामपुर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर घटना स्थल सहित आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।

भगवान श्री अग्रसेन प्रतिमा स्थापना आयोग के विजयराज बने प्रदेश संयोजक

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन से संबंद्ध छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल संगठन द्वारा विजयराज अग्रवाल को भगवान श्री अग्रसेन प्रतिमा स्थापना आयोग का प्रदेश संयोजक नियुक्त किया गया है। अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन से समबद्ध छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अग्रवाल रायपुर द्वारा विजयराज अग्रवाल की नियुक्ति की गई है। प्रदेश अध्यक्ष ने नियुक्ति प्रदान करते हुए विश्वास व्यक्त किया है कि विजयराज अग्रवाल के द्वारा पूरे प्रदेश के समस्त नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम एवं विकासखण्ड मुख्यालयों में भगवान महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा स्थापित हो। विजयराज अग्रवाल ने भगवान अग्रसेन की जीवनगाथा के बारे में बताते हुए कहा कि महाराजा अग्रसेन एक पूज्यनीय प्राचीन राजा थे, जो सामाजिक न्याय एवं सांप्रदायिक सद्भाव के सिद्धांतों के लिए जाने जाते थे। उन्हें अपने राज्य में समानता और कल्याण को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए याद किया जाता है, जिन्होने अग्रवाल समुदाय के उद्यमशीलता और परोपकार के मुल्यों की नींव रखी। उनके नेतृत्व और सुधारों ने सामाजिक मुल्यों पर अमिट प्रभाव छोड़ा है। भगवान अग्रसेन द्वारा व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना उनके शासन का एक और महत्वपूर्ण स्तंभ था। उन्होने आर्थिक गतिविधियों को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया, जिसने उनके राज्य की समृद्धि बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विजयराज अग्रवाल ने कहा कि हम उनके मार्गदर्शन एवं सान्निध्य में छत्तीसगढ़ राज्य में एक व्यापक अभियान प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके तहत प्रत्येक ग्राम व शहर में प्रमुख चौक चौराहों पर भगवान महाराजा अग्रसेन जी की संगमरमर की प्रतिमा स्थापित की जाएगी।

चुनापत्थर में 100 बोरी अवैध धान जब्त

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित बनाए रखने तथा अवैध धान परिवहन पर रोक लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में ग्राम चुनापत्थर में अवैध 100 बोरी धान जप्त किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, कल रात्रि ग्राम चुनापत्थर में जवाहिर पंडों के घर के बाहर लगभग 100 बोरी धान अज्ञात व्यक्ति द्वारा छोड़कर फरार हो गया।

मामले की सूचना मिलते ही तहसीलदार श्री अश्विनी चंद्रा, नायाब तहसीलदार श्री आई सी यादव सहित संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और मौके पर 100 अवैध बोरी धान को जप्त किया गया।

स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन एवं फिल्ड ऑफिसर के 115 पदों पर की जाएगी भर्ती

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। जिला रोजगार अधिकारी ने जानकारी दी है कि श्रमिन टैलेंट एवं स्वतंत्र माइक्रोफिन कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन एवं फील्ड ऑफिसर/कलेक्शन ऑफिसर के 115 पद पर भर्ती की जानी है। जिसके लिए जनपद पंचायत बलरामपुर के सभाकक्ष में 30 दिसम्बर को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया है। रोजगार विभाग के नवीन निर्देशानुसार रोजगार मेला/प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन वर्तमान में अनिवार्यत: ई-रोजगार पोर्टल पर ऑनलाईन मेला/प्लेसमेंट कैम्प क्रिएट कर किया जा रहा है। इसमें अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए आधार अपडेटेड जीवित रोजगार पंजीयन होना अनिवार्य है। जिन आवेदकों का वर्तमान में जीवित रोजगार पंजीयन नहीं हुआ है, वे ऑनलाईन रोजगार मेला/प्लेसमेंट कैम्प में आवेदन करने हेतु मतवरहंतण्बहण्हवअण्पद ध् बह तवरहंत ंचच के माध्यम से पहले रोजगार पंजीयन करना सुनिश्चित करें, तत्पश्चात मेला/प्लेसमेंट कैम्प हेतु उपलब्ध कराये गए लिंक में जाकर, रोजगार पंजीयन के आधार पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं, या प्लेसमेंट कैंप में 30 दिसम्बर 2025 को स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या के लिए मोबाइल नंबर 7587720774 पर संपर्क कर सकते हैं। योग्य अभ्यर्थी प्लेसमेंट कैम्प में निर्धारित दिनांक एवं स्थल में सम्पूर्ण दस्तावेज के साथ उपस्थित होकर रोजगार से जुड़ सकते हैं।

शिविर में 88 महिलाओं ने कराया स्वास्थ्य परीक्षण

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान के तहत दशहरा मैदान केंद्रीय चिकित्सालय के सामने शिवानी महिला मंडल द्वारा महिलाओं के लिए नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच एवं दवा वितरण शिविर का आयोजन किया गया।यह आयोजन श्रद्धा महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती शशि दुहन के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। शिविर की शुरुआत करते हुए शिवानी महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती अल्पना सिंह ने कहा कि महिलाओं का उत्तम स्वास्थ्य ही सशक्त परिवार और मजबूत समाज की आधारशिला है। शिविर में महिलाओं की सामान्य स्वास्थ्य जांच, चिकित्सकीय परामर्श तथा नि:शुल्क दवाओं का वितरण किया गया। इस अवसर पर 88 महिलाओं ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। कार्यक्रम को सफल बनाने में महिला मंडल की सुनीता कुमारी, जया रामन्ना, महिमा सिंह, निशा श्रीवास्तव एवं ज्योति शर्मा का विशेष योगदान रहा। शिविर में एएमओ डॉ. यूएस बैठा, डॉ. संगीता, डॉ. सत्यपाल, डॉ. हर्षवर्धन सहित अस्पताल के अन्य स्टाफ ने अपनी सेवाएं प्रदान कर महिलाओं को आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श दिया। शिवानी महिला मंडल ने महिलाओं से ऐसे स्वास्थ्य शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाने और अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की अपील की है।

राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के पारंपरिक वेशभूषा में जिला रहा प्रथम

सूरजपुर। प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन 23 से 25 दिसंबर तक राज्य खेल प्रशिक्षण केन्द्र, बहतराई बिलासपुर में किया गया। इस महोत्सव में प्रदेश के विभिन्न जिलों से चयनित प्रतिभागियों ने सहभागिता की। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में जिला से प्रथम स्थान प्राप्त दल ने भाग लिया और विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। विशेष रूप से पारंपरिक वेशभूषा प्रतियोगिता में सूरजपुर जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया। इस प्रतियोगिता में रणविकास सिंह आरमों ने प्रथम स्थान तथा वर्षा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। प्रतिभागियों के इस उत्कृष्ट प्रदर्शन पर कलेक्टर एस. जयवर्धन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत विजेंद्र सिंह पाटले द्वारा उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी गईं।

फेडरेशन के हड़ताल से दफ्तरों में छाई वीरानी, कामकाज हुआ प्रभावित

11 सूत्रीय मांगों को लेकर 3 दिवसीय आंदोलन पर है अधिकारी कर्मचारी

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। अपनी 11 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन 3 दिनों की हड़ताल पर चले गए है। सोमवार को पहले दिन हड़ताली कर्मचारियों ने पुराना बस स्टैंड परिसर में धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद किया। इस दौरान बड़ी संख्या में फेडरेशन के पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। हड़ताल के पहले दिन से ही दफ्तरों में वीरानी छाई रही और काम के लिए आये लोग भटकते नजर आए। पदाधिकारियों ने बताया कि उनकी लंबित 11 सूत्रीय मांगों पर शासन द्वारा कोई ठोस निर्णय न होने से कर्मचारियों में भारी नाराज़गी है, जो अब आंदोलन के रूप में सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर तीन दिन का पूर्ण कामबंद और कलमबंद आंदोलन करने का ऐलान किया है।

अधिकारियों का आरोप है कि केंद्र के समान देय तिथि से लाभ न मिलने के कारण उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।बार-बार ज्ञापन सौंपने के बावजूद शासन के उपेक्षापूर्ण रवैये ने अब उन्हें हड़ताल जैसा कड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने सरकार के लगातार उपेक्षापूर्ण रवैये के विरोध में 3 दिवसीय हड़ताल पर है। फेडरेशन के अनुसार शासन द्वारा बारंबार पत्राचार एवं एक दिवसीय हड़ताल के बावजूद लंबित मांगों पर कोई सकारात्मक पहल नहीं होने से संगठन आंदोलन को बाध्य हुआ है। फेडरेशन के जिला संयोजक डॉ आर एस सिंह ने बताया कि पूर्व में फेडरेशन के द्वारा प्रथम चरण में मशाल रैली, द्वितीय चरण में एक दिवसीय ध्यानाकर्षण रैली व तृतीय चरण में तीन दिवसीय निश्चितकालीन आंदोलन किया जा रहा है,फिर भी सरकार सकारात्मक समाधान नहीं करती तो अंतिम चरण में अनिश्चितकालीन आंदोलन करने को बाध्य होंगे। मोदी की गारंटी के अनुरूप कर्मचारियों को देय 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता तथा लगभग 80 माह का लंबित एरियर्स जीपीएफ खाते में समायोजित करने सहित 11 सूत्रीय मांगों पर सरकार उदासीन है। इसी के चलते फेडरेशन को 29 से 31 दिसंबर तक 3 दिन की हड़ताल के लिए मजबूर होना पड़ा है।

बताया गया है कि जिले के समस्त अधिकारी, कर्मचारियों ने अपने अपने विभाग प्रमुख को इसकी सूचना दे दी है।

ये हैं फेडरेशन की प्रमुख मांगें

केंद्र के समान देय तिथि से कर्मचारियों व पेंशनरों को महंगाई भत्ता । वर्ष 2019 से लंबित महंगाई भत्ता एरियर्स को जीपीएफ में समायोजित करना। सभी संवर्गों को चार स्तरीय समयमान वेतनमान लिपिक, शिक्षक, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास सहि विभिन्न विभागों की वेतन विसंगति दूर करना तथा पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनि करना। प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा लाभ की गणना सहायक शिक्षक, पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों को तृतीय समयमान सहित अन्य मांगें शामिल हैं।

महुली उप स्वास्थ्य केंद्र के एएनएम अटैचमेंट, बिगड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

चांदनी बिहारपुर। सूरजपुर जिले के दूरस्थ, पहाड़ी एवं आदिवासी बाहुल चांदनीङ्कबिहारपुर क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। क्षेत्र में पहले से ही स्वास्थ्य कर्मियों की कमी बनी हुई है, इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा पदस्थ एएनएम को मनमाने ढंग से अन्य स्थानों पर अटैच कर दिया गया, जिससे महुली उप स्वास्थ्य केंद्र का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। सूत्रों के अनुसार, उप स्वास्थ्य केंद्र महुली में नियुक्त सेकंड एएनएम को पुन: दूसरे स्थान पर अटैच कर दिया गया, जिसके कारण यहां बीते एक वर्ष से डिलीवरी सेवा पूरी तरह बंद है। यही नहीं, इससे पहले भी यहां पदस्थ एएनएम को अटैच कर अन्यत्र भेज दिया गया था, जिसके बाद से टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की जांच सहित अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं भी नियमित रूप से संचालित नहीं हो पा रही हैं। स्वास्थ्य कर्मियों की कमी के कारण गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी, टीकाकरण, प्रसव पूर्व एवं पश्चात जांच, नवजात शिशु देखभाल तथा प्राथमिक उपचार जैसी मूलभूत सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो चुकी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मजबूरी में महिलाओं को प्रसव के लिए 10 से 15 किलोमीटर दूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिहारपुर जाना पड़ता है, जहां

एक साल से डिलीवरी बंद, शोपीस बना केंद्र ग्रामीणों में आक्रोश

भी समय पर सुविधा मिलना मुश्किल हो जाता है। स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव और क्षेत्र के सीमावर्ती होने के कारण अधिकांश गर्भवती महिलाओं को पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले के बैढ़न तक ले जाया जा रहा है। नजदीकी होने से अब कई महिलाओं का प्रसव छत्तीसगढ़ के बजाय मध्यप्रदेश में हो रहा है, जो राज्य सरकार की मातृ-शिशु स्वास्थ्य योजनाओं और प्रशासनिक दावों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार 24 नवम्बर 2025 को आदेश क्रमांक 7136 जारी किया गया था, जिसमें सुमन साहू द्वितीय एएनएम की मूल पदस्थापना उप स्वास्थ्य केंद्र महुली में दर्ज है। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा उन्हें अन्य स्थान पर अटैच कर दिया गया, जिससे महुली उप स्वास्थ्य केंद्र में डिलीवरी और टीकाकरण सेवाएं वर्षों से प्रभावित बनी हुई हैं। बता दें कि महुली उप स्वास्थ्य केंद्र पर महुली, कोल्हूआ, चोगा, करौटी, खोहीर, रामगढ़, बैजनपाठ, लूल्ह, तेलाईपाठ, भून्डा, कछवारी, जूडवनीया सहित एक दर्जन से अधिक गांव निर्भर हैं, लेकिन केंद्र के निष्क्रिय होने से ग्रामीण बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों की इस कथित मनमानी को लेकर ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने मांग की है कि अटैच किए गए एएनएम कर्मियों को तत्काल उनके मूल पदस्थापन स्थल पर वापस भेजा जाए, दूरस्थ क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त स्वास्थ्य स्टाफ की स्थायी नियुक्ति की जाए, केंद्र में बिजली, पानी एवं प्रसव सुविधा तुरंत बहाल की जाए। जिससे क्षेत्र के लोगो को समुचित स्वास्थ्य सुविधा मिल सके।

महावीरगंज में आजीविका डबरी निर्माण पर तकनीकी मार्गदर्शन

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा के निर्देशन एवं जिला पंचायत श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर के मार्गदर्शन में जनपद पंचायत रामचन्द्रपुर के ग्राम पंचायत महावीरगंज में आजीविका डबरी निर्माण की तकनीकी जानकारी दी गई इसके साथ ही ले-आउट के बारे मे मार्गदर्शन दिया गया।इसके अंतर्गत डबरी निमार्ण के लिए स्थल चयन, माप-मान, खुदाई, ढलान, लाइनिंग, इनलेट-आउटलेट, ओवरफ्लो, सुरक्षा उपाय तथा रख-रखाव से संबंधित विस्तृत तकनीकी जानकारी दी गई। जारी किये गये लेआउट के अनुसार डबरी की मानक लम्बाई-चौड़ाई-गहराई निर्धारित की गई है। प्रमुख तकनीकी बिन्दु स्थल का चयन निम्न ढाल वाला क्षेत्र, जल भराव योग्य भूमि, सुरक्षित दूरी पर बस्तियों

मानक आकार के बारे में विस्तार से बताया गया। आजीविक डबरी निर्माण से वर्षा का जल संचयन, मत्स्य पालन, सिंचाई एवं पशुपालन को बढ़ावा देने के साथ ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि करना है, इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, तकनीकी सहायक, बी.एफ.टी., ग्राम रोजगार सहायक, मेट एवं मनरेगा श्रमिक उपस्थित रहे।

पंचदेव बस्ती में हुआ भव्य हिंदू महासम्मेलन का आयोजन

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर। हिंदू जन जागरण समिति पंचदेव बस्ती के द्वारा हिंदू महासम्मेलन का आयोजन रविवार को यहां के पंचमन्दिर पारा स्थित माँ दुर्गा पंडाल में किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में समरसता स्थापित करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के द्वारा भारत माता की पूजन एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया।इस दौरान मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह जिला कार्यवाह विजय शर्मा ने अपने वक्तव्य में कहा कि संघ के शताब्दी वर्ष की उपलक्ष्य में समाज के द्वारा हिंदू महासम्मेलन का आयोजन हिंदू समाज में समरसता का भाव प्रकट करने, भेद, भिन्नता को समाप्त करने और अपनी संस्कृति, परंपरा के प्रति गौरवान्वित अनुभव करें, इस प्रकार के आयोजन देश के प्रत्येक मंडल, नगर बस्ती पर देखने को मिल रहा है, हिंदू धर्म जिसे हम सनातन धर्म के नाम से जानते हैं, जब से सृष्टि का जन्म हुआ है और जो संस्कृति इस सृष्टि में प्रथम रूप में आई वह हिंदू संस्कृति सनातन संस्कृति के रूप में हम समझ सकते हैं क्योंकि सबसे पुरातन संस्कृति सनातन संस्कृति जिसका आदि है ना अंत, जो संस्कृति है वह सनातन- हिंदू संस्कृति ही है। हिंदू समाज को सारे भेद भूलकर मूल हिंदुत्व की भावना को जीवन में धारण करना होगा। पंच परिवर्तन के पांच बिंदु सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, कुटुंब प्रबोधन, स्व आधारित जीवन एवं नागरिक कर्तव्य बोध को समाज अपने जीवन में आत्मसात करें, भारत का जन-जन पंच परिवर्तन के बिंदुओं को धारण करेगा तो भारत अपने गौरव को पुनः प्राप्त कर विश्व गुरु के स्थान को प्राप्त करेगा।मातृशक्ति के रूप मे उपस्थित डॉ शिवांजलि सिंह ने परिवार में संस्कार एवं संयुक्त भाव हो, परिवार

को जोड़ने हेतु छोटा-छोटा प्रयास हमारा हो भोजन, भजन किसी कारणवश व्यस्तता के नियमित नहीं हो रहा है तो कम से कम सप्ताह में एक बार पूरा परिवार एक साथ भोजन, भजन करें क्योंकि परिवार चरित्रवान होगा तो हमारा देश भी मजबूत और ताकतवर होगा। कार्यक्रम के अतिथि संत श्री स्वामी पुरी जी महाराज ने अपने वक्तव्य में कहा कि अपनी संस्कृति का सम्मान अपने बड़ों के सम्मान के बराबर है, हम सभी भारत माता की संतान है, इस प्रकार हमारे सभी भेद भिन्नता समाप्त हो जाते हैं और हम सभी एक हैं। नन्ही बच्ची सुश्री श्रेजल गुप्ता के द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा चलाए गए पंच परिवर्तन को संक्षिप्त में क्रमशः जानकारी दी, और समाज इसे स्वयं में धारण करें।कार्यक्रम में सभी समाज के प्रमुखो का समिति ने आमंत्रित कर साल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। जिसमें जनजाति समाज से अकालु सिंह, नाई समाज से संतोष ठाकुर, धोबी समाज लाल बाबू रजक, यादव समाज से रामदेव यादव, कुशवाहा समाज से रामकुमार कुशवाहा, साहू समाज से जोखन लाल साहु , देवांगन समाज से परशुराम देवांगन , राजवाडे समाज से नानराम राजवाड़े, विश्वकर्मा समाज से नारद विश्वकर्मा , सोनी समाज से विक्रम सोनी , हलवाई समाज से गणेश गुप्ता , जायसवाल समाज से डॉ. प्रकाश जयसवाल , सौंडिक समाज से एच.एन. गुप्ता , कसेरा समाज से ज्वाला प्रसाद गुप्ता, कहार समाज से कमलेश कोसरिया , अग्रवाल समाज से वेद प्रकाश बंसल, ब्राह्मण समाज से राम बिलास शर्मा एवं अन्य समाज के लोग भी उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़िया गीत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में कर्मा लोक नृत्य एवं सुआ लोक नृत्य के अलग-अलग दल ने अपना जोरदार प्रदर्शन किया जो पूरे कार्यक्रम का आकर्षण का केंद्र रहा। अंतिम में इन्हें सम्मान हेतु स्मृति चिन्ह भेंट किया गया।

9वीं सीनियर राष्ट्रीय गतका चैंपियनशिप में सरगुजा के दो खिलाड़ियों का चयन

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। 9वीं सीनियर राष्ट्रीय गतका चैंपियनशिप 2025झ26 का आयोजन 28 से 30 दिसंबर 2025 तक चंडीगढ़ में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता के लिए सरगुजा जिले से दो खिलाड़ियों का चयन छत्तीसगढ़ प्रदेश गतका टीम में हुआ है, जो जिले के लिए गौरव का विषय है। राष्ट्रीय कोच राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ टीम के सीनियर वर्ग में सरगुजा जिले से सुष्मिता चौहान एवं शिवरतन का चयन उनके निरंतर अच्छे प्रदर्शन के आधार पर किया गया है। सरगुजा गतका कोऑर्डिनेटर रजत सिंह ने कहा कि गांधी स्टेडियम स्थित

बास्केटबॉल ग्राउंड में नियमित रूप से गतका का अभ्यास कराया जाता है, जहां से लगातार खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आगे चलकर खेलो इंडिया जैसे आयोजनों में भाग लेने का अवसर भी मिल सकता है। इस अवसर पर द गतका एसोसिएशन सरगुजा के सभी पदाधिकारियों, प्रशिक्षकों एवं खिलाड़ियों ने चयनित दोनों खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

कर्तव्य पथ पर दिखेगा जनजातीय वीर नायकों को समर्पित देश का पहला डिजिटल संग्रहालय

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर।आगामी गणतंत्र दिवस समारोह में नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर छत्तीसगढ़ की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र बनेगी। इस वर्ष छत्तीसगढ़ की झांकी में जनजातीय वीर नायकों को समर्पित देश के पहले डिजिटल संग्रहालय की अद्भुत झलक प्रदर्शित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति द्वारा गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह के लिए छत्तीसगढ़ की झांकी का चयन किया गया है।उल्लेखनीय है कि यह डिजिटल संग्रहालय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर नवा रायपुर अटल नगर में लोकार्पित किया जा चुका है। गणतंत्र दिवस समारोह हेतु झांकी के चयन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बधाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की झांकी के माध्यम से देशभर के नागरिकों को आदिवासी समाज की अटूट देशभक्ति, अनुपम वीरता और अपने सिद्धांतों के लिए बलिदान की गौरवशाली परंपरा को देखने का अवसर मिलेगा। उन्होंने इसे पूरे राज्य के लिए गर्व और उत्साह का विषय बताया।जनसंपर्क विभाग के सचिव रोहित यादव ने बताया कि सभी राज्यों द्वारा अपनी झांकियों के प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेजे गए थे।

अखिल भारतीय आदिवासी बिंझिया समाज महासंघ का वार्षिक महासम्मेलन ग्राम लक्ष्मणगढ़ में आयोजीत

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। अखिल भारतीय बिंझिया समाज महासम्मेलन की राष्ट्रीय बैठक का आयोजन छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला के लक्ष्मणगढ़ में हुआ। युक्त बैठक बिंझिया समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूवाल सिंह सिरदार सहित सामाज के पदाधिकारियों की उपस्थिति में हुई। आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज, विधायक प्रतिनिधि विजय अग्रवाल,नीरज अग्रवाल, उदयपुर सरपंच संघ के अध्यक्ष प्रदीप मरकाम, उदयपुर मंडल अध्यक्ष अखंड विधायक सिंह, प्रबोद सिंह, सहित अन्य जनप्रतिनिधियों रहे। वही बिंझिया सामाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूवाल सिंह सिरदार, राष्ट्रीय सचिव हरदेव सिरदार,व राष्ट्रीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष विजय सिरदार, उपाध्यक्ष नरसिंह नारायण सिंह,राष्ट्रीय सलाहकार दिलीप साय सिरदार,राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष देवनारायण पटवारी, युमो सचिव कैलाश सिरदार, राष्ट्रीय युवा मोर्चा प्रवक्ता देवशरण सिरदार,युमो प्रदेश अध्यक्ष देवेन्द्र सिरदार जिला पंचायत सदस्य श्रीमती नयन विजय सिरदार,जनपद सदस्य सूरजपुर अनीता सुरेश सिरदार, संभागीय अध्यक्ष बुझन राम सिरदार, जयनगर क्षेत्र अध्यक्ष लाल बहादुर सिरदार, संगठन मंत्री

अनिल सिंह, राष्ट्रीय युवा मोर्चा महामंत्री राजेश्वर सिरदार, कुंवरपुर बइगा आलम साय सिरदार,राष्ट्रीय युवा मोर्चा सह प्रवक्ता कृष्णा पाल, राष्ट्रीय युवा मोर्चा मीडिया प्रभारी भरत सिदार, राष्ट्रीय युवा मोर्चा सह मीडिया प्रभारी सितेश सिरदार,फुलेश्वर सिरदार, फलेश्वर सिरदार, तेजाराम, एवं हमारे छत्तीसगढ़ के चार क्षेत्र के अध्यक्ष जयनगर क्षेत्र से लाल बहादुर सिरदार, कलुआ क्षेत्र से शिवमल सिरदार, भटगांव क्षेत्र से एच आर प्रधान, डभरा क्षेत्र से संजय सिरदार रहे, कार्यक्रम की शुरूवात सर्वप्रथम मां भारती एवं हमारे समाज के धरती आंबा एवं हमारे पूर्वज भगवान गोपाल राय जी की छाया चित्र पर दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया, एवं समस्त अतिथियों का फुलमाला एवं बुके द्वारा स्वागत अभिनन्दन किया गया। स्वागत भाषण युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय सिरदार के द्वारा दिया गया, तत्पश्चात हमारे बिंझिया समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूवाल सिंह सिरदार व सांसद,मंत्री प्रतिनिधि सहित समाज के प्रतिनिधि व क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने पुलिस आरक्षक में चयन हुए सभी आरक्षकों को बधाई शुभकामनाओं के साथ सम्मानित किया गया।इस महा सम्मेलन में समाज को एकजुट होने की बात कही गई, नशा को दूर किया जाए, सहित समाज के अनेक कुरुतियों के बारे में चर्चा की गई, इस दौरान असम, उड़ीसा झारखंड, रायपुर सहित आसपास क्षेत्र के कई समाज के सामाजिक कार्यकर्ता, बिंझिया समाज मंत्री अमरनाथ सिरदार, मंत्री गीता राम सिरदार,मंत्री गणेश सिरदार, दयाल सिरदार,महामंत्री तेज बहादुर सिंह, मंत्री विवेक सिरदार, सह प्रवक्ता छबिशंकर सिरदार, मंत्री राम सिंह, मंत्री सुरेश सिरदार, कार्यकारिणी सदस्य में धनसार, ब्रह्मदेव, छत्रपाल सिरदार, गेंदालाल, देवप्रताप, भोजराज, सांझू राम, राजेन्द्र प्रसाद, दयाल, सिरदार, सुखलाल सिरदार, पुरषोत्तम सिरदार, विनोद सिरदार रहे।

मतदाता जागरूकता हेतु आयोजित की गई पेंटिंग प्रतियोगिता

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिले में मतदाता सूची के अद्यतन एवं मतदाता जागरूकता को लेकर विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की गईं। तहसील ओडगी में बीएलओ की बैठक आयोजित कर फॉर्म-6 कलेक्शन की समीक्षा की गई।इस दौरान बीएलओ नो-मैपिंग मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए तथा लॉजिकल त्रुटियों के सुधार हेतु को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।इसी क्रम में तहसीलदार की उपस्थिति में जनपद सभा कक्ष, भैयाथान में समस्त बीएलओ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में फॉर्म-6 का कलेक्शन एवं ऑनलाइन एंट्री,नो-मैपिंग

मतदाताओं को नोटिस ,लॉजिकल त्रुटि सुधार, अन्य संबंधित विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अघिना सलका में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके अलावा विद्यालय में 27 बच्चों को चिन्हांकित कर फॉर्म-6 का वितरण किया गया।इसके साथ ही तहसील भटगांव के बतरा में मतदाता जागरूकता के तहत पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें फॉर्म-6 हेतु 120 बच्चों को चिन्हांकित कर फॉर्म वितरित किए गए।इसके अतिरिक्त सरस्वती शिशु मंदिर, जरही में बच्चों को फॉर्म-6 की जानकारी दी गई। यहां 17 बच्चों को चिन्हांकित कर फॉर्म-6 का वितरण किया गया। इन गतिविधियों के माध्यम से जिले में मतदाता सूची को शुद्ध एवं अद्यतन करने के साथ-साथ युवा मतदाताओं को जागरूक करने की दिशा में प्रभावी पहल की जा रही है।

प्रधानमंत्री से परीक्षा पे चर्चा हेतु जिले को मिला 96 हजार का लक्ष्य, 38 हजार ने कराया रजिस्ट्रेशन

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देशभर के विद्यार्थियों, शिक्षकों और पालकों को सीधे संवाद करने का एक और सुनहरा अवसर मिल रहा है। प्रतिवर्ष की भाँति इस वर्ष भी परीक्षा पे चर्चा के भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जो इस श्रंखला का 9 वाँ संस्करण होगा।इस मंच के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यों से चयनित बच्चों द्वारा परीक्षा से संबंधित पूछे गए सवालों के जवाब देकर उनका मार्गदर्शन करेंगे और उनके तनाव को कम करने का प्रयास करेंगे।इस कार्यक्रम में कक्षा 6 से 12 वीं के विद्यार्थी, शिक्षक

और अभिभावक सभी अपने प्रश्न अधिकतम 5 सौ शब्दों में तैयार कर सकते हैं।प्रश्न अपलोड करने की सुविधा भारत सरकार के पोर्टल पर उपलब्ध है। परीक्षा पे चर्चा विकल्प में प्रतिभागी पुरस्कारों से जुडी तिथियों और अन्य दिशा-निर्देशों की जानकारी देख सकते हैं। कार्यक्रम के लिए प्रश्न अपलोड करने की प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू हो चुकी है और प्रतिभागी अपने प्रश्न 11 जनवरी तक अपलोड कर सकते है। आपको बता दें कि कलेक्टर एस जयवर्धन के मार्गदर्शन में जिला सूरजपुर का शिक्षा एवं समग्र शिक्षा विभाग ने विशेष रणनीति बना कर अधिकतम छात्रों को परीक्षा पर चर्चा में रजिस्ट्रेशन करने का अभियान चलाया है।जिले को 96 हजार लक्ष्य परीक्षा पर चर्चा का रजिस्ट्रेशन का मिला हुआ है। विभाग से मिली प्राप्त अंतिम जानकारी तक 40 प्रतिशत से ज्यादा यानी 38 हजारे छात्रों अभिभावकों एवं शिक्षकों ने परीक्षा पर चर्चा का रजिस्ट्रेशन कराया है गत दिनों ₹वीर बाल दिवस समारोह₹ के अवसर पर एक ही दिन में 9.5 हजार से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ जो लक्ष्य का 10 प्रतिशत है। 26 नवंबर को प्रदेश भर में एक दिन में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन करने का रिकॉर्ड स्थापित हुआ। परीक्षा पर चर्चा मे खंड स्तरीय शिक्षा अधिकारी, संकुल समन्वयक और शिक्षकों ने सभी 6 से 12 कक्षा तक के छात्र छात्राओं का शत प्रतिशत रजिस्ट्रेशन के लिए प्रयासरत हैं। परीक्षा एक ऐसा विषय है जिस पर सुनते ही मानसिक तनाव, असहजता एवं डर का वातावरण छात्रों में रहता है इसी डर को दूर करने के लिए परीक्षा पर चर्चा में रजिस्ट्रेशन कर करके छात्र प्रधानमंत्री से सीधे संवाद स्थापित करेंगे एवं लाइव प्रसारण भी देख सकेंगे, जिससे उनके मन में तनाव , भय आदि का वातावरण दूर होकर के स्वस्थ प्रतियोगात्मक परीक्षा में भाग लेंगे और अच्छे नंबर ला सकते हैं।

यूपी में कड़ाके की सर्दी का कहर, बर्फीली हवाओं से बढ़ी गलन

मैदानी इलाकों में दिख रहा पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप लगातार बढ़ रह है। लखनऊ में सुबह से बादल छाए रहे। बफीर्ली हवाओं के असर से गलन बढ़ी। इस बीच ठंड से बचने के लिए लोग अलाव तापते नजर आए। मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, बिजनौर सहित प्रदेश के 45 जिले घने कोहरे की चपेट में हैं। इनमें से 18 जिलों में दृश्यता शून्य तक पहुंच गई है।हालात ऐसे हैं कि सड़कों पर वाहन बेहद धीमी रफ्तार से चल रहे हैं और कई जगह सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। ओस की बूंदें बारिश जैसी गिर रही हैं, जिससे गलन और ठंड और ज्यादा बढ़ गई है।

मौसम वैज्ञानिक अतुल सिंह ने बताया कि पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में साफ दिख रहा है। इसके चलते अगले तीन दिनों में दिन और रात दोनों समय ठंड और बढ़ेगी और राहत की कोई संभावना नहीं है। कोहरे की वजह से रेलवे स्टेशनों पर 50 से अधिक ट्रेनें 2 से 10 घंटे की देरी से चल रहीं हैं।इस वजह से यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा, जिससे भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक भयंकर ठंड और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि बेवजह यात्रा न करें और सतर्कता बरतें। मौसम विभाग के अनुसार धूप निकलने की संभावना बेहद कम है। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को मौसम पर लगातार नजर रखने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि बदलते तापमान और कोहरे से फसलों में कीट और रोग बढ़ सकते हैं, इसलिए समय रहते उपाय जरूरी हैं।

रविवार को अधिकतम तापमान 15.3 व न्यूनतम 10.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए प्रदेश में कोल्ड डे और अत्यंत घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। ठंड से लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए प्रदेश में कोल्ड डे और अत्यंत घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच पूर्वी यूपी के बलिया में बूंदाबांदी से मौसम का मिजाज एकदम से बदल दिया है।

ठंड और गलन बढ़ गई है। शीतलहर से लोग कांपते दिखाई दिए। रात से ही आसमान में बादल छाए रहे। बेमौसम बरसात से तिलहनी और दलहनी की खेती किये किसानों की चिंताएं बढ़नी शुरू हो गयी है। सड़कों पर मौजूद लोग जगह-जगह अलाव का सहारा लेते नजर आये। घरों में भी रजाई और कंबल लोगों का सहारा बने। वैसे तो पिछले कई दिनों से ठंड ने जोर पकड़ा हुआ है।

कान्हा गोशाला में लगे हीटर, राहत दे रहे अलाव

नगर निगम प्रशासन ने बढ़ती सर्दी और शीतलहर को देखते हुए आमजन और गोवंशों के लिए हर संभव राहत के उपाय किए हैं। नगर आयुक्त के निर्देश पर गोशालाओं में हीटर लगाए गए हैं और अलाव की व्यवस्था की गई है। पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा ने बताया सरोजनीनगर में स्थित कान्हा गौशाला में लगभग 10 हजार गोवंश संरक्षित हैं, जिनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रशासन की प्राथमिकता है। लगातार बढ़ती सर्दी और शीतलहर में सर्दी से गोवंशों को राहत दिलाने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। गोशालाओं में 200 से अधिक परदे लगाए गए हैं, 20 हीटर लगवाए गए हैं, ताकि गोवंशों को ठंड से सुरक्षित रखा जा सके। इसके साथ ही 28 बाडों में 53 अलाव की व्यवस्था भी की गई है। इसी जरह शहर में अलग-अलग कांजी हाउस में जब्त किए गए पशुओं को ठंड से बचाव के लिए अलाव जलाए जा रहे हैं। पशु कल्याण अधिकारी ने बताया सर्दी को देखते हुए लगातार निरीक्षण भी किया जा रहा है। जरूरत होने पर परदे, हीटर व अलाव की संख्या बढ़ाने को कहा गया है।

नगर निगम जला रहा हजार स्थलों पर अलाव

नगर निगम की ओर से नागरिको को सार्वजनिक स्थानों पर ठण्ड से बचाये जाने के लिए रैन बसेरो की व्यवस्था की गयी है। समस्त क्षेत्रों में 100 से अधिक स्थाई व अस्थाई रैन बसेरे संचालित व क्रियाशील है। यहां निराश्रितों को आश्रय की व्यवस्था के लिए सभी आवश्यक सुविधायें यथा- बेड, बिस्तर, नहाने के गर्म पानी के लिए गीजर, कमरे को गर्म रखने के लिये ब्लोवर, शौचालय की व्यवस्था एवं साफ-सफाई की अनिवार्य रूप से समुचित व्यवस्था करायी गयी है। इसके अतिरिक्त आश्रयहीन, रैन बसेरों में ठहरे व्यक्तियों, रेलवे स्टेशनो के आगन्तुकों, अस्पताल एवं चौराहों पर आने-जाने वाले व्यक्तियों को ठण्ड से बचाव के लिए जगह-जगह 1056 अलाव जलाये जाने की व्यवस्था भी की गई है।

निर्विवाद में मानवीय संवेदना और प्रकृति प्रेम का रेखांकन

लखनऊ। ख़्वाजा मुनिउद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के अटल सभागार में युवा कवि पवन कुमार सिंह के काव्य संग्रह निर्विवाद और अन्य कविताएं का विमोचन और परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति अजय तनेजा ने की।

इस कार्यक्रम में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर जनार्दन, त्रिपुरा केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर मनोज कुमार मौर्य, केंद्रीय उच्च तिब्बती संस्थान वाराणसी के प्रोफेसर सुशील कुमार सिंह, किसान पीजी कॉलेज के हिंदी विभाग के प्रोफेसर चन्द्रदेव सिंह,कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कवि एवं शायर प्रोफेसर बलवंत सिंह ने पवन कुमार सिंह की कविताओं पर अपने विचार व्यक्त किये। इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह ने किया।

पवन कुमार सिंह के कविता संग्रह में निहित मानवीय संवेदना, प्रकृति प्रेम को रेखांकित करते हुए इन वक्ताओं ने इस संग्रह को कविता की दुनिया मे एक जरुरी हस्तक्षेप माना। अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में कुलपति प्रोफेसर अजय तनेजा ने पवन की कविताओं में निहित संवेदना को महत्वपूर्ण माना।

अरावली पहाड़ियों से जुड़ा मुद्दा इन दिनों केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह एक बड़े सामाजिक–राजनीतिक आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इसे पर्यावरण संरक्षण का गंभीर सवाल बता रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार इसे खनन माफिया पर सख्त प्रहार के रूप में पेश कर रही है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा से यह सवाल उठ रहा था कि क्या अरावली के माध्यम से खनन उद्योग को गति प्रदान की कोशिश हो रही है ? हालांकि सरकार यह प्रदर्शित कर रही है कि वह खनन को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है, लेकिन क्या इन प्रयासों से वास्तव में नियमानुसार खनन हो पाएगा ? माना जा रहा है कि अरावली की नई परिभाषा से इन पहाड़ियों में खनन और तेज हो जाएगा और पहाड़ियां खत्म होने के कगार पर पहुंच जाएंगीं। यह थार रेगिस्तान को पूर्वी भारत की ओर बढ़ने से रोकने में एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करती है। यही कारण है कि इसे उत्तर भारत का "रक्षा कवच" भी कहा जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार अरावली पर्वत श्रृंखला केवल जीव-जंतुओं के लिए ही नहीं, बल्कि इंसानों के लिए भी एक लाइफ लाइन है। अब सबसे अहम यह है कि क्या सचमुच अरावली का भविष्य सुरक्षित है? इसी का विश्लेषण करता *आजकल* का यह खास अंक...

अरावली के अस्तित्व पर संकट

विश्लेषण

रवि शंकर

स्वतंत्र पत्रकार

देश में बढ़ते विकास के बीच जंगल, पहाड़ अक्सर अपनी कुर्बानी देते हैं भारत में इसका सबसे ताजा उदाहरण अरावली है जो विकास बनाम पर्यावरण के बीच खड़ी है। करीब 690 किलोमीटर लंबी अरावली, जो गुजरात से शुरू होकर राजस्थान और हरियाणा होते हुए दिल्ली तक फैली है। इसने सदियों से उत्तर-पश्चिमी भारत में जलवायु संतुलन और बायोडायवर्सिटी को बचाए रखा है। आज अरावली एक बार फिर विकास, पर्यावरण संरक्षण और कानून के टकराव के बीच में खड़ी है। अरावली का महत्व सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं है। यह थार रेगिस्तान को पूर्वी भारत की ओर बढ़ने से रोकने में एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करती है। यही कारण है कि इसे उत्तर भारत का "रक्षा कवच" भी कहा जाता है। पर्यावरण के लिहाज से अरावली भूजल को रिचार्ज करने में मदद करती है, जिससे राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर में पानी का संतुलन बना रहता है।

करीब 690 किलोमीटर लंबी अरावली, जो गुजरात से शुरू होकर राजस्थान और हरियाणा होते हुए दिल्ली तक फैली है। इसने सदियों से उत्तर-पश्चिमी भारत में जलवायु संतुलन और बायोडायवर्सिटी को बचाए रखा है। आज अरावली एक बार फिर विकास, पर्यावरण संरक्षण और कानून के टकराव के बीच में खड़ी है। आज, अरावली रेंज खतरे में है। अवैध माइनिंग ने 20 फीसदी इलाके को नष्ट कर दिया है। वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि यहां के जंगलों को बचाना और उनका विस्तार करना बहुत ज़रूरी है। माइनिंग को कंट्रोल करना भी ज़रूरी है

प्रदूषण रोकने में मददगार

ये पहाड़ियां धूल भरी आंधियों को रोकती हैं और प्रदूषण को सोखकर दिल्ली-एनसीआर की हवा को साफ रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि अगर अरावली कमजोर हुई तो रेगिस्तान फैल सकता है और उत्तर भारत में जल संकट और गंभीर हो जाएगा।एक ओर अरावली को उत्तर भारत के पर्यावरणीय संतुलन के लिए बेहद अहम बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे प्रदेश के भविष्य से जुड़ा मुद्दा बनाकर सड़क से सदन तक संघर्ष की तैयारी में जुट गया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर, 2025 में अरावली की परिभाषा बदल दी, जिसमें 100 मीटर से ऊंची जगहों को ही पहाड़ी माना जाएगा। इस आदेश से सिर्फ राजस्थान के 15 जिलों में 12,081 पहाड़ियों में से केवल 1,048 (8.7 फीसदी) ही इस मानक को पूरा कर सकेंगी और 90 फीसदी से अधिक क्षेत्र संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएगा। यही बात पर्यावरणविदों को चिंता में डाल रही है। उनका कहना है कि सिर्फ़ ऊँचाई के आधार पर अरावली को परिभाषित करने से कई ऐसी पहाड़ियों पर खनन और निर्माण के लिए दरवाज़ा खुल जाने का खतरा पैदा हो जाएगा, जो 100 मीटर से छोटी हैं, झाड़ियों से ढंकी हुई और पर्यावरण के लिए जरूरी हैं।

जनजीवन से जुड़ा है मामला

यह फैसला सिर्फ कानूनी व्याख्या का मामला नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन, पर्यावरण व भविष्य से जुड़ा सवाल है। इसलिए पर्यावरणविद मांग कर रहे हैं कि सरकार अरावली क्षेत्रों को वैज्ञानिक मानकों से परिभाषित करे, जिसमें उसका भूगोल, पर्यावरण. वन्यजीव संपर्क और जलवायु संघर्ष क्षमता शामिल हो। हालांकि, सरकार और कुछ कानून विशेषज्ञों का कहना है कि नई परिभाषा 1980 के दशक से चली आ रही, जो इस लड़ाई पर एक सामान्य परिभाषा बनाएगी। कोर्ट ने भी माना कि पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ आर्थिक वास्तविकताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अरावली क्षेत्र में पत्थर और खनिजों का खनन हजारों लोगों की आजीविका से जुड़ा है और बुनियादी ढांचे के लिए जरूरी है। बिना ठोस वैज्ञानिक और कानूनी आधार के पूरी तरह से प्रतिबंध के कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं।केंद्र सरकार का कहना है कि नई परिभाषा का मकसद नियमों को मज़बूत करना और एकरूपता लाना है, न कि सुरक्षा को कम करना। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि यह मान लेना ग़लत है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली हर जमीन पर खनन की इजाज़त होगी।

अब अरावली की नई परिभाषा

पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि 1,47,000 वर्ग किलोमीटर में फैली अरावली श्रृंखला का सिर्फ़ दो फीसदी हिस्सा ही संभावित रूप से खनन के लिए इस्तेमाल हो सकता है और वह भी विस्तृत अध्ययन और आधिकारिक मंजूरी के बाद। बहरहाल, अरावली पर्वत श्रृंखला के संरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश और केंद्र सरकार द्वारा अरावली की नई परिभाषा तय करने के प्रयासों के बाद राजस्थान की राजनीति गरमा गई है। इस पूरे विवाद की जड़ में एक सबसे अहम सवाल है, जो देखने में सरल लेकिन असल में बेहद खतरनाक है- आखिर अरावली की कानूनी और पर्यावरणीय परिभाषा क्या होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने जो नई परिभाषा पर मुहर लगाई है क्या वो पर्यावरण मानकों और साइंटफिक स्केल के दायरे में किया गया है? यह सवाल इसलिए अहम बन जाता है क्योंकि इसी परिभाषा के आधार पर यह तय होता है कि कौन-सा क्षेत्र खनन, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या संरक्षण के दायरे में आएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार की सुझाई गई परिभाषा को स्वीकार किए जाने के बाद यह बहस और तीखी हो गई है। अरावली का महत्व केवल स्थानीय नहीं, बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर भी अत्यंत व्यापक है। यह पर्वतमाला थार मरुस्थल और उत्तर भारत के घनी आबादी वाले मैदानों के बीच एक प्राकृतिक ढाल की तरह काम करती है। राजस्थान, दिल्ली और गुरुग्राम जैसे क्षेत्रों में यह धूल भरी हवाओं को रोकने, तापमान नियंत्रित करने और वर्षा के जल को जमीन में समाहित करने में सहायक है। अरावली के जंगल कार्बन अवशोषण और वायु शुद्धिकरण में भी अहम भूमिका निभाते हैं। यदि अरावली को गंभीर क्षति पहुंचती है, तो इसके परिणाम दूरगामी होंगे। विशेषज्ञों के अनुसार इससे वायु प्रदूषण में वृद्धि, भीषण गर्मी और हीटवेव, और भूजल स्तर में तेज गिरावट जैसी समस्याएं और गहराएंगी।

माइनिंग कंट्रोल करना ज़रूरी

यह राजस्थान में मरुस्थलीकरण की गति बढ़ सकती है, जबकि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण और जल संकट और गंभीर रूप ले सकता है। अरावली पर सुप्रीम कोर्ट की नई परिभाषा ने एक ऐसे निर्णायक मोड़ की ओर संकेत किया है, जहां कानूनी व्याख्या और पर्यावरणीय वास्तविकता के बीच संतुलन स्थापित करना अनिवार्य हो गया है। आने वाले समय में इस फैसले के प्रभाव केवल कानून की किताबों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उत्तर भारत के पर्यावरण और जनजीवन पर गहरी छाप छोड़ सकते हैं। दरअसल, यह पूरा मामला दिखाता है कि अरावली संरक्षण की लड़ाई लंबी है। विकास और पर्यावरण का संतुलन कैसे बनेगा, यह समय बताएगा। लेकिन आज, अरावली रेंज खतरे में है। अवैध माइनिंग ने 20 फीसदी इलाके को नष्ट कर दिया है। सरकार अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट चला रही है। वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि यहां के जंगलों को बचाना और उनका विस्तार करना बहुत ज़रूरी है। माइनिंग को कंट्रोल करना भी ज़रूरी है।

जीवन के लिए पर्वतीय श्रृंखला का जिंदा रहना जरूरी

मुद्दा

सुशील देव

वरिष्ठ स्तंभकार

अरावली पहाड़ियों से जुड़ा मुद्दा इन दिनों केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह एक बड़े सामाजिक–राजनीतिक आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इसे पर्यावरण संरक्षण का गंभीर सवाल बता रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार इसे खनन माफिया पर सख्त प्रहार के रूप में पेश कर रही है। दशकों से चल रही राजनीति, विरोधाभासी फैसलों और बदलती परिभाषाओं के बीच यह सवाल सबसे अहम है कि क्या सचमुच अरावली का भविष्य सुरक्षित है? हाल ही में केंद्र सरकार ने अरावली पहाड़ियों में नए खनन मामलों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली–एनसीआर तक फैली पूरी अरावली श्रृंखला पर लागू किया गया है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो खदानें पहले से संचालित हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार सभी पर्यावरणीय मानकों और सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन करना होगा। सरकार का दावा है कि इससे प्रकृति को हो रहे नुकसान को रोका जाएगा और अरावली क्षेत्र में हरियाली लौटाने के प्रयास किए जाएंगे। इसी बीच अरावली की परिभाषा को लेकर विवाद गहरा गया है। हालिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि केवल वही भूमि अरावली पहाड़ी मानी जाएगी, जो आसपास की जमीन से कम से कम 100 मीटर ऊंची हो।

यदि अरावली कमजोर होती है, तो दिल्ली–एनसीआर जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पानी और हवा दोनों का संकट और गहरा सकता है। पहले ही गुरुग्राम, फरीदाबाद और आसपास के इलाकों में अरावली की कई पहाड़ियां कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो चुकी हैं।

इस परिभाषा के सामने आते ही पर्यावरणविदों और विपक्षी दलों ने आशंका जताई कि इससे बड़ी संख्या में छोटी पहाड़ियां, टीले और झाड़ियों से ढके क्षेत्र संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगे। कांग्रेस का आरोप है कि नई परिभाषा के तहत अरावली का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा संरक्षित नहीं रह पाएगा और उसे रियल एस्टेट या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए खोला जा सकता है। सरकार इन आरोपों को सिरे से खारिज करती है। उसका कहना है कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है और खनन पर लगे प्रतिबंध से बौखला गया है। पर्यावरण मंत्रालय का दावा है कि अरावली के संरक्षण के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और सर्वे ऑफ इंडिया को नई परिभाषा के आधार पर नक्शा तैयार करने के निर्देश केवल स्पष्टता के लिए दिए गए हैं। बावजूद इसके, इस मुद्दे पर देशभर में विरोध प्रदर्शन, हस्ताक्षर अभियान और जनसभाएं हो रही हैं, जो बताती हैं कि जनता की चिंता गहरी है। अरावली मानसून के दौरान बादलों की दिशा मोड़ने में अहम भूमिका निभाती है, जिससे पूर्वी राजस्थान और उत्तरी मैदानों को वर्षा मिलती है। यह थार मरुस्थल के विस्तार को रोकती है और रेत–धूल को दिल्ली–एनसीआर तक पहुंचने से काफी हद तक थामे रखती है। इसके अलावा, अरावली को भूजल रिचार्ज का इंजन भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में मौजूद जंगल, चट्टानें और मिट्टी वर्षा जल को जमीन में समाहित कर जलस्तर बनाए रखने में मदद करते हैं।

यदि अरावली कमजोर होती है, तो दिल्ली–एनसीआर जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पानी और हवा दोनों का संकट और गहरा सकता है। पहले ही गुरुग्राम, फरीदाबाद और आसपास के इलाकों में अरावली की कई पहाड़ियां कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो चुकी हैं। इतिहास पर नजर डालें तो अरावली को लेकर राजनीतिक दलों की भूमिका भी सवालों के घेरे में रही है। आरोप है कि 2003 में कांग्रेस सरकार के दौरान 100 मीटर ऊंचाई वाली परिभाषा की नींव रखी गई थी, जिसे 2010 में सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। तब अदालत ने उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। अब करीब 14 साल बाद वही परिभाषा एक बार फिर सामने आई और सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई। इस कारण विपक्ष और पर्यावरणविद् दोनों सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। सच्चाई यह है कि अरावली को सबसे ज्यादा नुकसान राजनीति से ज्यादा लालच और अनियंत्रित विकास ने पहुंचाया है। खनन, रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचे के नाम पर इस पर्वतमाला को लगातार काटा गया। नतीजा यह है कि दिल्ली–एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक बना रहता है और लोगों की औसत आयु तक प्रभावित हो रही है। आज जरूरत इस बात की है कि अरावली को केवल राजनीतिक बहस का विषय न बनाकर राष्ट्रीय धरोहर के रूप में देखा जाए। वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों और स्थानीय समुदायों की राय को गंभीरता से सुना जाए। विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाना ही एकमात्र रास्ता है। क्योंकि सच यही है-अगर अरावली जिंदा रहेगी, तभी हमारी हवा, पानी और जीवन भी सुरक्षित रह पाएगा।

अरावली बचाने की मुहिम पर सवाल उठाना गलत

विवाद

रोहित कौशिक

स्वतंत्र पत्रकार

अरावली पर चले रहे विवाद के बीच केन्द्र सरकार ने राज्यों को अरावली में नए खनन पट्टे देने पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि यह रोक पूरे अरावली क्षेत्र पर समान रूप से लागू होगी और इसका मकसद इस क्षेत्र की अखंडता को बनाए रखना है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा से यह सवाल उठ रहा था कि क्या अरावली के माध्यम से खनन उद्योग को गति प्रदान की कोशिश हो रही है ? हालांकि सरकार यह प्रदर्शित कर रही है कि वह खनन को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है लेकिन क्या इन प्रयासों से वास्तव में नियमानुसार खनन हो पाएगा ? माना जा रहा है कि अरावली की नई परिभाषा से इन पहाड़ियों में खनन और तेज हो जाएगा और अरावली की पहाड़ियां खत्म होने के कगार पर पहुंच जाएंगीं, जिससे कई तरह के पर्यावरणीय बदलाव होंगे। मुख्य रूप से राजस्थान में अरावली की नई परिभाषा को लेकर आन्दोलन तेज हो गया है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में अरावली की पहाड़ियां हैं लेकिन राजस्थान में अरावली की 80 प्रतिशत पहाड़ियां हैं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की पहाड़ियों में अवैध खनन को रोकने के लिए केन्द्र सरकार से जवाब मांगा था। कोर्ट का कहना था कि अरावली की पहाड़ियों को लेकर कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। सभी राज्य अपने अनुसार यह तय करते हैं कि वे किस पहाड़ को पहाड़ मानेंगे और किस पहाड़ पर खनन करने की इजाजत देंगे। इसी संशय को दूर करने के लिए केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एक समिति बनाई। इस समिति ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी सिफारिशें दाखिल कीं। केन्द्र सरकार ने इस सिफारिशों में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यदि किसी पहाड़ की ऊंचाई 100 मीटर या उससे ज्यादा है तो उस पहाड़ से 500 मीटर के इलाकों को अरावली क्षेत्र माना जाएगा और वहां किसी भी प्रकार के खनन की अनुमति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए कहा कि जो पहाड़ इस परिभाषा के हिसाब से अरावली क्षेत्र में नहीं आएंगे, वहां सस्टेनेबल माइनिंग यानी टिकाऊ खनन हो सकेगा। सस्टेनेबल माइनिंग का अर्थ यह है कि खनन करते हुए वहां के पर्यावरण, जल, जंगल और जनता की जिंदगी को स्थायी हानि न हो। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। लोगों का मानना है कि इस परिभाषा के हिसाब से अरावली के 90 प्रतिशत पहाड़ खत्म हो जाएंगे क्योंकि इन पहाड़ों की ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा नहीं है। यह सही है कि अरावली क्षेत्र में पहले से ही खनन होता रहा है लेकिन अब समाज में अरावली को बचाने की चिंता देखी जा रही है तो इस चिंता को कठघरे में खड़ा नहीं किया जाना चाहिए।

सस्टेनेबल माइनिंग का अर्थ यह है कि खनन करते हुए वहां के पर्यावरण, जल, जंगल और जनता की जिंदगी को स्थायी हानि न हो।

देश में तमाम प्राकृतिक धरोहरों को संभालना होगा

सियासत

योगेश कुमार सोनी

वरिष्ठ पत्रकार

हाल ही में राजस्थान में अरावली की पहाड़ियां इन दिनों सियासत की जंग का मैदान बनी हुई हैं। अरावली को लेकर सब अपने-अपने हिसाब से परिभाषित कर रहे हैं जिसे लेकर जबरदस्त विवाद छिड़ा हुआ है। आरोप-प्रत्यारोप का खेल भी जमकर हो रहे हैं। भाजपा आरोप लगा रही है कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत जो 'सेव अरावली' कैंपेन चला रहे थे, वह उन्हीं के कार्यकाल में अरावली 100 मीटर की परिभाषा की सिफारिश की गई थी और हमने वो ही किया।

हमें पहले यह समझना चाहिए कि अरावली भारत की रीढ़ है जो चार राज्यों से गुजरती है। यह उत्तर-पश्चिम भारत में लगभग 670 किलोमीटर लंबी मानी जाती है। यह दिल्ली के पास से शुरू होकर दक्षिण हरियाणा और राजस्थान के अंदर तक जाती है और फिर गुजरात में अहमदाबाद के आसपास के मैदानों तक पहुंचती है।

भूगोलविद सीमा जालान बताती हैं कि अरावली 67 करोड़ वर्ष पुरानी पर्वतमाला है और यह नहीं होतीं तो उत्तर भारत की जाने कितनी नदियां नहीं होतीं। जाने कितने जंगल, कितनी वनस्पतियां, कितने बहुमूल्य धातु और कितने इकोलॉजिकल वैभव नहीं होते। विशेषज्ञों के अनुसार अरावली पर्वत श्रृंखला केवल जीव-जंतुओं के लिए ही नहीं बल्कि इंसानों के लिए भी एक लाइफ लाइन है। सरकार इस मुद्दे की गंभीरता को समझे। जिस तरह केंद्र सरकार ने अरावली पहाड़ियों को 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली घोषित किया गया है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी। इसके अलावा हरियाणा सरकार के हस्तक्षेप करने का कारण यह है कि अरावली का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा ही हरियाणा में आता है और बाकि हिस्सा राजस्थान में है। जनता का आरोप है कि बीते कई वर्षों से अरावली की चोरी हो रही है और 100 मीटर बने

आज जब अरावली की समस्या आई तो हर कोई अपनी उपस्थिति दर्ज करा है लेकिन यह सबको पता है कि कोई भी प्राकृतिक व ऐतिहासिक धरोहर नष्ट या क्षतिग्रस्त एकदम या कुछ समय में नहीं होती।

कानून का कोई औचित्य नहीं है। वहीं, दूसरी ओर सरकार ने इसकी पैरवी की और ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के जरिए की जा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि एक तरफ देश में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार अरावली जैसी प्राकृतिक दीवार को कमजोर करने का काम कर रही है।

पहले ही अरावली में बड़े स्तर पर अवैध खनन हो रहा है। बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसे में कैसे बचेगी अरावली और कैसे बचेगा पर्यावरण? बहरहाल, आज जब अरावली की वजह से प्राकृतिक समस्या आई तो हर कोई अपनी उपस्थिति दर्ज करा है लेकिन यह सबको पता है कि कोई भी प्राकृतिक व ऐतिहासिक धरोहर नष्ट या क्षतिग्रस्त एकदम या कुछ समय में नहीं होती। इसमें लंबा समय लगता है और यह खुला खेल हमेशा शासन-प्रशासन के सामने ही होता रहा है। मौजूदा स्थिति में हाईटेक होने के लिए हर रोज विश्व का एक सकारात्मक दिशा की ओर निर्माण हो रहा है जिसमें भारत का नाम भी बेहद चुनिंदा देशों में गिना जाने लगा। हम अन्य देशों की अपेक्षा पर्यावरण व प्राकृतिक धरोहरों को बचाने व संभालने में उतने सक्षम नहीं हैं जितने कि हमें जरूरत है। दरअसल मामला यह है कि लगातार बढ़ रही जनसंख्या को व्यवस्थित करने के लिए हम पर्यावरण व धरोहरों का विनाश करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मानव जीवन की सबसे अहम व मूलभूत जरूरत को दरकिनार करके तरक्की करना अपराध सा लगता है।

हमारे यहां जनसंख्या का तेजी से बढ़ना जारी है तो उस आधार पर सरकारों को जनता के लिए जगह की व्यवस्था करनी होती है जिसके चलते जंगल का पर्यावरण व पहाड़ों को बर्बाद किया जा रहा है देश की तरक्की व जनता की जरूरत के लिए ऐसे मुद्दों की गंभीरता न समझना मानव जीवन पर ही भारी पड़ रहा है। वैज्ञानिकों ने लगातार हो रही आपदाओं के लिए प्राकृतिक संसाधनों के अधिक इस्तेमाल को जिम्मेदार ठहराया है। उनका मानना है कि आज स्थिति के आधार पर हमारी धरती अपने भार से कहीं अधिक भार वहन कर रही है। अगर यही हाल रहा तो अगले कुछ वर्ष बाद ही धरती रहने लायक नहीं बचेगी।

आजादी की लड़ाई से लेकर देश के नवनिर्माण तक कांग्रेस

स्थापना दिवस

दीपक बैज

कांग्रेस ने अपनी स्थापना के 140 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 141वें स्थापना दिवस की आप सभी को बधाई। आज भले ही अधिकांश राज्यों में कांग्रेस की सरकार नही है, लेकिन कांग्रेस ही देश का एक मात्र राजनैतिक दल है जिसका कार्यकर्ता भारत के उत्तर, दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम के हर गांव में मिल जाएगा। 28 दिसंबर 1885 को कुछ बुद्धिजीवियों ने भारत के लोगों की जरूरतों, उनकी समस्याओं के विमर्श के लिए एक मंच की जरूरत महसूस की, जो तत्कालीन हुक्मरानों के समक्ष भारत की जनता की आवाज बन सके, सरकार के द्वारा बनाई जा रही नीतियों में भारतीयों की जरूरतों को स्थान दिलवाया जा सके। इन्ही उद्देश्यों को लेकर 72 सदस्यों ने कांग्रेस की स्थापना की जिनमें एओ ह्यूम, दादाभाई नौरोजी, व्योमेश चन्द्र बेनर्जी, काशीनाथ तेलंग, राघवाचारी प्रमुख थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन व्योमेश चन्द्र बेनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई में हुआ। भारतीयों की समस्याओं को उठाने के उद्देश्य के लिए गठित की गई कांग्रेस पार्टी बहुत जल्दी ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की मुखर विरोधी बन गयी। गठन से लेकर भारत की आजादी तक कांग्रेस के लगभग 15 मिलियन सदस्य बन गए थे।

गुलाम भारत के लोगों में राजनैतिक चेतना जागृत कर उनमें आजाद मुल्क की ललक पैदा करना एक बड़ा कठिन काम था, जब तक लोगों में आजादी और स्वराज की जरूरत की चेतना जागृत नहीं होगी, अंग्रेजी शासन के खिलाफ कोई भी आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता, इस बात को कांग्रेस ने भली भांति समझ लिया था, इसीलिए कांग्रेस ने शुरू से ही अंग्रेजी हुकूमत के विरोध के कार्यक्रमों में आम आदमी को जोड़ा और सामूहिक नेतृत्व पर जोर दिया। 1915 में महात्मा गांधी के भारत आगमन के बाद उन्हें कांग्रेस की अध्यक्षता सौंपी गयी, 1919 में गांधी जी कांग्रेस के प्रतीक पुरुष बन गए और इसके बाद कांग्रेस ने देश भर में अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों के खिलाफ जनांदोलनों को खड़ा करना शुरू किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा दिया और रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया।

कांग्रेस आजादी का लक्ष्य प्राप्त करने में इसलिए सफल हुई क्योंकि वह लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर आगे बढ़ रही थी। आजादी की लड़ाई में कांग्रेस किसी एक वर्ग की नही बल्कि सम्पूर्ण भारत की अगुवाई कर रही थी। कांग्रेस में कई विचार धाराएं थी, गांधी जी सहित कांग्रेस के नेतृत्वकर्ताओ ने वैचारिक मतभिन्नता का पूरा सम्मान किया तथा विभिन्न विचारों को लेकर स्वतंत्र भारत के एक लक्ष्य के साथ कांग्रेस दुनिया के सबसे बड़े सफल अहिंसक आंदोलन को चलाने में कामयाब हुई। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कांग्रेस भारत के जनमानस की आईना थी। सारा भारत कांग्रेस के साथ था सिर्फ साम्प्रदायिक जातिवादी और अंग्रेजो के प्रति श्रद्धा रखने वाले संगठन जरूर कांग्रेस के खिलाफ थे।

आजादी के बाद छोटे बड़े रजवाड़ो रियासतों को समाहित कर लोकतांत्रिक भारत के निर्माण के साथ समानता वाले भारत का निर्माण, सबको समान आणथक अवसर के साथ धार्मिक, सामाजिक और लैंगिक समानता को सुनिश्चित करना बहुत बड़ी चुनौती थी। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जानते थे कि यह सारे लक्ष्य तभी फलीभूत हो सकते है जब भारत आर्थिक रूप से सुदृढ और सुरक्षित हो, स्वस्थ हो। इसीलिये नेहरू जी ने सिचाई परियोजनाओं के साथ बड़े कल कारखानो की नींव साथ में रखी। नेहरू जी ने विज्ञान और संस्कृति के सामंजस्य वाले भारत की कल्पना की थी। यही कारण था कि उन्होंने देश में आईआईएम, आईआईटी जैसे अभियांत्रिकी प्रबन्ध संस्थानों से लेकर बेहतरीन चिकित्सा संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की। पंडित नेहरू के बाद की कांग्रेस सरकारों ने उनके द्वारा स्थापित इस मजबूत नीव पर आधुनिक भारत की शानदार इमारत की स्थापना पर कोई कसर नही छोड़ी।

नेहरू जी के बाद शास्त्री जी के समय अनाज की उपलब्धता बढ़ाई, देश की सुरक्षा को लक्ष्य रख कर जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। इंदिरा जी हरित क्रांति, बीस सूत्री कार्यक्रम, अंतरिक्ष कार्यक्रम, परमाणु कार्यक्रम से सुदृढ़ भारत के लक्ष्य को प्राथमिकता में रखा। राजीव गांधी जब भारत के प्रधानमंत्री बने तब देश को 21वीं सदी की ओर ले जाने के लिए कांग्रेस की प्राथमिकता में सूचना प्रोद्योगीकी और कम्प्यूटर क्रांति थी, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 करके युवाओं को लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने का अवसर दिया, पंचायतों को सशक्तीकरण कर सत्ता के विकेंद्रीकरण का मार्ग भी खोला गया। पीवी नरसिंहराव जी के समय आर्थिक उदारीकरण को अपना कर वैश्विक व्यापारिक जगत में भारत को मजबूती से खड़ा करने का प्रयास किया गया। यूपीए चेयर पर्सन श्रीमती सोनिया गांधी के मार्गदर्शन तथा मनमोहन सिंह के नेतृत्व में आर्थिक सुधारों के साथ खाद्य सुरक्षा कानून, सूचना के अधिकार, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी, शिक्षा का अधिकार, भू–अधिग्रहण जैसे कानूनों को लाकर कांग्रेस ने आम आदमी के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास किया।

2014 में केंद्र की सत्ता तथा 2023 में राज्य की सत्ता हाथ से जाने के बाद कांग्रेस एक सजग विपक्ष की भूमिका निभा रही है। बहुमत के अतिवादी चरित्र का विरोध जिस बेबाकी और निडरता से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे जी कर रहे है वह कांग्रेस के उन्ही मूल्यों उपज है जिन मूल्यों को लेकर कांग्रेस ने दुनियां के सबसे बड़े लोकतांत्रिक आंदोलन और भारत के सबसे बड़े राष्ट्रवादी आंदोलन से भारत की आजादी की लड़ाई को लड़ा था। लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाकर पाटऍ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे अनुभवी शख्स को पार्टी के निचले पायदान ब्लाक अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना कांग्रेस जैसे दल में ही संभव है। आजादी की लड़ाई का प्रमुख हथियार नेशनल हेराल्ड तथा यंग इंडिया जैसे देश और कांग्रेस की अमूल्य धरोहरों को लेकर केंद्र की सत्तारूढ़ दल भाजपा के द्वारा षड़यंत्र किया गया। कांग्रेस के नेतृत्व पर प्रहार किया गया। आजादी की लड़ाई के इन प्रतिमानों यंग इंडिया और नेशनल हेराल्ड को बचाने के प्रयासों को ही अपराध साबित करने की कुचेष्टा की गई, लेकिन अदालत में यह षड़यंत्र बेनकाब हो गया।

कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने देश के मजदूरों और वंचित वर्ग के लोगों को रोजगार मुहैया कराने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श के अनुरूप मनरेगा कानून का निर्माण किंया था, वर्तमान केंद्र सरकार ने मनरेगा कानून की मूल आत्मा को नष्ट करने के लिए संसद में नया विधेयक पारित करवाया। इस कानून में महात्मा गांधी के नाम को हटा दिया गया। साथ ही मनरेगा कानून में मजदूरों के लिए रखे गये प्रावधानों को खत्म कर दिया गया। कांग्रेस महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप देश के अंतिम आदमी के साथ हमेशा खड़ी रही है। ऐसे तत्वों को ऐसी कुचेष्टा का हमेशा से विरोध करती रही है। इस षड़यंत्र से कांग्रेस का देश में सर्वधर्म सम्भाव, सर्वजनहिताय के लक्ष्य को प्राप्त करने का ईरादा कमजोर नहीं होगा।

(लेखक छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं)

मन की बात में बोले पीएम मोदी

स्वतंत्रता सेनानियों, वैज्ञानिकों और युवा शक्ति ने देश को गौरवान्वित किया

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के 129वें एपिसोड में देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इस साल सेना का शौर्य बना ऑपरेशन सिंदूर, स्वतंत्रता सेनानी पार्वती गिरि, एंटीबायोटिक दवाओं, कश्मीर के बारामूला में मिले बौद्ध स्तूपों के अवशेष और देश में युवा की भागेदारी समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी पार्वती गिरी को याद किया। गणतंत्र दिवस पर हमारा मन स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता के भाव से भर जाता है। दुर्भाग्य से आजादी के अनेक नायक-नायिकाओं को उचित सम्मान नहीं मिला।

प्रधानमंत्री ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के 129वें एपिसोड में देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इस साल सेना का शौर्य बना ऑपरेशन सिंदूर, स्वतंत्रता सेनानी पार्वती गिरि, एंटीबायोटिक दवाओं, कश्मीर के बारामूला में मिले बौद्ध स्तूपों के अवशेष और देश में युवा की भागेदारी समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत की।

भारत ने सुरक्षा, खेल, विज्ञान और वैश्विक मंचों पर

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा से लेकर खेल के मैदान तक, विज्ञान की प्रयोगशालाओं से लेकर दुनिया के बड़े मंचों तक भारत ने हर जगह अपनी मजबूत छाप छोड़ी।ऑपरेशन सिंदूर' हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बना। दुनिया ने साफ देखा कि आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान देश के कोने-कोने से मां भारती के प्रति प्रेम और समर्पण की तस्वीरें सामने आईं। लोगों ने अपने-अपने तरीके से अपने भाव व्यक्त किए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2025 खेल के लिहाज से भी यादगार साल रहा। पुरुष क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियन्स ट्रॉफी जीती और महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप अपने नाम किया।

बिना सोचे-समझे एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन न करें

पीएम मोदी ने कहा कि बिना सोचे-समझे एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन न करें। एंटीबायोटिक ऐसी दवाएं नहीं हैं, जिन्हें यूं ही ले लिया जाए। इनका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए।

भारत की उम्मीदों की वजह युवा शक्ति

पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया भारत को नई आशा के साथ देख रही है और भारत की उम्मीदों की वजह इसकी युवा शक्ति, विज्ञान और तकनीक में हमारी उपलब्धि है।

'तमिल सीखें- तमिल करकलम' से जुड़े कई स्कूल

प्रधानमंत्री ने इस साल वाराणसी में हुए 'काशी तमिल संगमम' में तमिल भाषा सीखने को लेकर बात कही। 'तमिल सीखें- तमिल करकलम' थीम के तहत वाराणसी की 50 से ज्यादा स्कूलों में विशेष अभियान चलाए गए।

दुबई में कन्नड़ सिखाने-पढ़ाने वाले परिवारों को सराहा

प्रधानमंत्री ने दुबई में कन्नड़ भाषा सिखाने-पढ़ाने वाले परिवारों की सराहना की है। पीएम मोदी ने कहा है कि कन्नड़ परिवारों की पहल से एक हजार से ज्यादा बच्चे जुड़े हैं, जो गर्व की बात है। अपनी जड़ों से जुड़े रहने के प्रयास वैश्विक हैं। प्रवासी भारतीय भी इसमें सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

सांस्कृतिक केंद्र बना 'गीतांजलि आईआईएससी'

प्रधानमंत्री ने 'गीतांजलि आईआईएससी' ग्रुप की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि 'गीतांजलि आईआईएससी' यह अब सिर्फ एक क्लास नहीं, बल्कि कैंपस का सांस्कृतिक केंद्र है।

खबर संक्षेप

31 दिसंबर तक करा लें आधार-पैन लिंक

नई दिल्ली। नए साल शुरू होने में गिने दिन बचे हैं। नए साल से कई बड़े बदलाव होने की संभावना है।

नए साल जनवरी से कारें महंगी हो रही हैं। कुछ काम ऐसे हैं, जिसे निपटाने का आखिरी मौका 31 दिसंबर तक है। जिनका आधार कार्ड 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले बना है, वे लोग 31 दिसंबर तक पैन से लिंक करा लें।

नायडू ने राममंदिर में किया दर्शन-पूजन

अयोध्या। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू रामनगरी अयोध्या पहुंचे। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर

प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्त और डीएम निखिल टीकाराम फुंडे ने स्वागत किया। यहां से वह राम मंदिर के लिए रवाना हुए। राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन और पूजन किया।

दिल्ली में नितिन को मिला नया आवास

नई दिल्ली। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को दिल्ली में नया आवास मिल गया है। उन्हें

लुटियंस जोन में सरकार द्वारा एक बंगला आवंटित किया

पीएम मोदी ने की मुख्य सचिवों की बैठक की अध्यक्षता की

प्रशासन सुधार, मानव पूंजी विकास, शिक्षा स्किलिंग,आत्मनिर्भर भारत पर दिया जोर

उद्देश्य-केंद्र और राज्यों को देश की राष्ट्रीय ग्रोथ के लिए प्राथमिकताओं को एक साथ लाना

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

〉भारत मंडपम में किया गया कार्यक्रम 〉परफॉर्मेंस और गवर्नेंस पर की चर्चा 〉 नीति आयोग द्वारा किया गया आयोजन

'विकसित भारत के लिए मानव पूंजी' थी थीम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की पांचवीं बैठक की। यह कार्यक्रम अभी भारत मंडपम में चला। इस कार्यक्रम का मकसद केंद्र और राज्यों को देश की राष्ट्रीय ग्रोथ के लिए अपनी प्राथमिकताओं को एक साथ लाना है।

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने 'ज्ञानवर्धक' बातचीत की, जिसमें भारत के प्रशासनिक सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए सुधार और परफॉर्मेंस के महत्व पर जोर दिया गया।

पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली में हुए मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान गवर्नेंस और सुधारों से जुड़े अलग-अलग मुद्दों पर ज्ञानवर्धक चर्चा हुई। सम्मेलन में मानव पूंजी विकास, शिक्षा, स्किलिंग, टेक्नोलॉजी, आत्मनिर्भर भारत और सुधार परियोजनाओं पर चर्चा हुई। इसके अलावा, राज्यों की कई समस्याओं पर भी सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच विचार विमर्श किया गया।

राज्यों में डीरेगुलेशन, गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी पर भी की बात

इस साल का सम्मेलन 'विकसित भारत के लिए मानव पूंजी' थीम पर आधारित है और इसमें शुरुआती बचपन की शिक्षा, स्कूली शिक्षा, स्किलिंग, उच्च शिक्षा और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में विकास पर फोकस करने वाले फोरम शामिल हैं। इस सम्मेलन में राज्यों में डीरेगुलेशन, गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रोजेक्ट्स पर भी चर्चा शामिल है। यह कार्यक्रम नीति आयोग द्वारा आयोजित किया गया।

मानव पूंजी बढ़ाने रोडमैप तैयार किया

इस कार्यक्रम का मकसद भारत की मानव पूंजी की क्षमता को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए एक कॉमन रोडमैप को अंतिम रूप देना है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य सचिवों के साथ मानव पूंजी को बढ़ाने के साथ ही संतुलित रखने परप जोर दिया। सम्मेलन का मुख्य विषय ही रखा गया है- विकसित भारत के लिए मानव पूंजी, इसलिए चर्चा के प्रमुख बिंदुओं में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, स्कूली शिक्षा, कौशल विकास, उच्च शिक्षा, खेल और पाठ्येतर गतिविधियां (एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटिज) शामिल हैं।

प्रदेशों की बेस्ट प्रेक्टिस और रणनीतियों को भी जाना

केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों सहित विशेषज्ञों के बीच विचार-विमर्श के आधार पर विभिन्न प्रदेशों द्वारा अपनाई जाने वाली बेस्ट प्रेक्टिस और रणनीतियों को प्रदर्शित किया गया।

आत्मनिर्भर भारत पर भी किया मंथन

राज्यों में विनियमन में ढील, शासन में प्रौद्योगिकी, स्मार्ट वैल्यू चेन और एक राज्य-एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी तथा पोस्ट-एलडब्ल्यूई भविष्य की योजनाएं जैसे विषयों पर छह विशेष सत्र हुए।

6 विशेष सत्र आयोजित किए गए

सम्मेलन के दौरान 'आत्मनिर्भर भारत', 'स्वदेशी' और 'पोस्ट-एलडब्ल्यूई भविष्य' से जुड़ी योजनाओं जैसे विषयों पर छह विशेष सत्र आयोजित किए गए। इसके अलावा, भोजन सत्रों के दौरान विरासत और पांडुलिपि संरक्षण व डिजिटलीकरण तथा सभी के लिए आयुष-आधारित प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा वितरण में ज्ञान के एकीकरण जैसे विषयों पर भी विचार-विमर्श किया। मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन पिछले चार वर्षों से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है।

मंत्री शेखावत की सोनिया से अपील

नेहरू के पत्र और दस्तावेज पीएम संग्रहालय को लौटाएं

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से अपील की है कि वे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़े पत्र और दस्तावेज प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय (पीएमएमएल) को वापस लौटाएं। उन्होंने कहा कि ये दस्तावेज किसी एक परिवार या व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे देश की विरासत हैं।

एक साक्षात्कार में मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय की स्थापना नेहरू जी के निधन के बाद हुई थी। पहले इसे नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी (एनएमएमएल) कहा जाता था, जिसे 2023 में बदलकर पीएमएमएल कर दिया गया। इस संग्रहालय में सभी प्रधानमंत्रियों से जुड़े दस्तावेज सुरक्षित रखे जाते हैं।

'पीएमएमएल में कुल करीब 2.5 करोड़ दस्तावेज'

उन्होंने कहा कि 1970 से 1990 के बीच नेहरू जी से जुड़े गैर-सरकारी दस्तावेज, निजी पत्र, उन्हें मिले

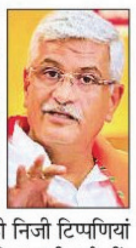

जवाब और उनकी निजी टिप्पणियां संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई थीं। पीएमएमएल में कुल करीब 2.5 करोड़ दस्तावेज हैं, जिनमें से लगभग 4 लाख दस्तावेज केवल पंडित नेहरू से जुड़े हैं।

पूर्व पीएम से जुड़े दस्तावेज किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं'

उन्होंने कहा कि 29 अप्रैल 2008 को सोनिया के निर्देश पर उनके प्रतिनिधि एमवी राजन ने पत्र लिखकर नेहरू के निजी पारिवारिक पत्र और नोट्स वापस मांगे थे। संग्रहालय से करीब 57 कार्टन, जिनमें लगभग 26000 दस्तावेज थे, परिवार को लौटा दिए गए। हमने इन दस्तावेजों को वापस लौटाने का अनुरोध किया है। सोनिया ने कहा है कि वह इस पर विचार करेंगी। ये दस्तावेज किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं हो सकते।

डिजिटलीकरण और पांडुलिपियों का संरक्षण

मंत्री ने बताया कि संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय अभिलेखागार में बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण अभियान शुरू किया है। लाखों फाइलों को डिजिटल रूप में सुरक्षित किया गया है, जो दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटलीकरण परियोजनाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि देश में लाखों प्राचीन पांडुलिपियां हैं, कुछ ताड़ के पत्तों, पेड़ की छाल, रेशम और हस्तलिखित कागज पर लिखी गई हैं। इन्हें संरक्षित करना बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'ज्ञान भारतम् मिशन' शुरू किया, जिसके तहत इन पांडुलिपियों को डिजिटाइज कर एक पोर्टल पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए एनएमएमटी की डेडिकेटेड अउ बस सेवा शुरू, 5 रूट, 14 बसें

नवी मुंबई : नवी मुंबई महानगरपालिका परिवहन उपक्रम ने गुरुवार सुबह से नवी मुंबई एयरपोर्ट के लिए डेडिकेटेड अउ बस सर्विस शुरू कर दी है। फिलहाल इस मार्ग पर अभी 2 बसों से शुरूआत की गई है। आने वाले कुछ दिनों के बाद इस सेवा का विस्तार किया जाएगा। यह नए टर्मिनल के लिए पहला फॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिंक होगा। एनएमएमटी से मिली जानकारी के अनुसार बस की सर्विस सुबह 6 बजे शुरू होंगी, जिन्हें 5 शटल रूट पर 14 बसों के शुरूआती फ्लीट से सपोर्ट मिलेगा। नई सर्विस का मकसद एयरपोर्ट और खास सबअर्बन रेलवे स्टेशनों के बीच आसान लास्ट माइल कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। बताया गया कि ट्रेन से सफर करने वाले पैसेंजर बेलापुर-नेरुल-उरण सबअर्बन कॉरिडोर पर तरघर रेलवे स्टेशन के जरिए भी एयरपोर्ट जा सकेंगे, जो टर्मिनल एंट्रेंस से करीब 1.5 किमी दूर है। सेंट्रल रेलवे ने एयरपोर्ट के चालू होने से पहले 15 दिसंबर को तरघर और आस-पास के गव्हाण स्टेशन खोल दिए थे ताकि आने-जाने वालों और यात्रियों को आसानी से आने-जाने में मदद मिल सके।

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग०

ईश्तहार

रा०प्र०क्र०-/अ-6/2025-26

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक उदय गुप्ता पिता रामलाल गुप्ता, उम्र-67 वर्ष, जाति सौण्डिक, निवासी चर्च रोड़ केदारपुर, अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के द्वारा तदाशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, कि अनावेदक रामलाल पिता प्रकाश राम, उम्र 86 वर्ष, जाति सौण्डिक, निवासी चर्च रोड केदारपुर, अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के द्वारा स्वयं के स्वामित्व व अधिपत्य की शीट नं. 03, मोहल्ला केदारपुर नगर अम्बिकापुर स्थित भूखण्ड क्रमांक 1139/7 रकबा 0.12 एकड़ में से रकबा 1584.6 तथा 1029 कुल 2613.6 वर्गफीट भूमि का पंजीबद्ध दानपत्र पंजीयन दिनांक 20.11.2025 का निष्पादन आवेदक के पक्ष में किया गया है। अतः उक्त पंजीबद्ध दान पत्र के आधार पर उक्त दानशुदा भूमि के नजूल अभिलेख में स्वयं का नाम दर्ज कराने हेतु आवेदक द्वारा पंजीबद्ध दान पत्र की छायाप्रति मय दस्तावेज सहित आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त सबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 16/01/ 2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/अपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक- 16/12/2025 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एंव हस्ताक्षर से जारी किया गया।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग०

ईश्तहार

रा०प्र०क्र०-/अ-6/2025-26

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक विनय गुप्ता पिता रामलाल गुप्ता, उम्र-63 वर्ष, जाति सौण्डिक, निवासी चर्च रोड केदारपुर, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.) के द्वारा तदाशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, कि अनावेदक रामलाल पिता प्रकाश राम, उम्र 86 वर्ष, जाति सौण्डिक, निवासी चर्च रोड़ केदारपुर, अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के द्वारा स्वयं के स्वामित्व व अधिपत्य की शीट नं. 03, मोहल्ला केदारपुर नगर अम्बिकापुर स्थित भूखण्ड क्रमांक 1139/7 रकबा 0.12 एकड़ में से रकबा 2613.6 वर्गफीट भूमि का पंजीबद्ध दानपत्र पंजीयन दिनांक 20.11.2025 का निष्पादन आवेदक के पक्ष में किया गया है। अतः उक्त पंजीबद्ध दान पत्र के आधार पर उक्त दानशुदा भूमि के नजूल अभिलेख में स्वयं का नाम दर्ज कराने हेतु आवेदक द्वारा पंजीबद्ध दान पत्र की छायाप्रति मय दस्तावेज सहित आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त सबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 16/01/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/अपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक- 16/12/2025 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एंव हस्ताक्षर से जारी किया गया।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अंबिकापुर, जिला सरगुजा, (छ०ग०)

ईश्तहार

रा०प्र०क्र०/अ-2/2025-26

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सोनी कुमारी पत्नी नीतिश जाति क्षत्रिय निवासी कन्या परिसर रोड़ अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०म०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आध्यि की भूमि स्थित ग्राम नमनाकला तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) खसरा नंबर 2/1028 रकबा 0.012 हे० भूमि को कृषि भिन्न आवासीय /व्यावसायिक प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए भूमि की बी-1, खसरा, नक्शा, ले-आउट, रजिस्ट्री की प्रति, आदि सहित आवेदन प्रस्तुत किया है. जो इस न्यायालय में विचाराधीन है।अतएव उक्त सबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो. तो निर्धारित सुनवाई तिथि 05/01/2026 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।आज दिनांक 19/12/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी
(रा). अम्बिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा

रा०प्र०क्र० //अ-20(3)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदिका मीरा अग्रवाल पत्नी स्व० संतलाल अग्रवाल उम्र लगभग 45 वर्ष जाति अग्रवाल निवासी खजूरपारा ब्रम्हरोड अम्बिकापुर थाना व तहसील अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा छ०ग० के द्वारा शीट नम्बर -8 मोहल्ला खजूरपारा नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल भूखण्ड क्रमांक 3105/2, 3106/1 रकबा क्रमशः 0.01, 0.02 एकड़ भूमि को अनावेदक/केता मीरा देवी गुप्ता पत्नी अखिलेश गुप्ता उम्र लगभग 41 वर्ष जाति केशरवानी निवासी केदारपुर त्रिकोण चौक अम्बिकापुर, थाना व तहसील अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा छ०ग० के पास बिक्रय करने की अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु मेन्टनेन्स खसरा, शपथ पत्र की छायाप्रति सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त भू-खण्ड के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा-आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 16/01/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांक 23/12/2025 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा सेजारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

इच्छुक हज यात्रियों और टूर ऑपरेटर्स से सऊदी अरब सरकार के नियमों का पालन करने की अपील

▫ फेडरेशन व एसोसिएशन का आह्वान, 15 जनवरी से पहले बुकिंग पंजीकरण अनिवार्य

मुंबई। आगामी वर्ष हज यात्रा पर जाने के इच्छुक यात्रियों तथा हज टूर ऑपरेटर्स से सऊदी अरब सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने और 15 जनवरी 2026 से पहले सीट बुकिंग का पंजीकरण पूरा करने की अपील फेडरेशन हज पीटीओज ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया हज एंड उमराह ऑर्गनाइजर एसोसिएशन ने की है। इस संबंध में मुंबई के मराठी पत्रकार संघ में एक पत्रकार परिषद आयोजित की गई, जिसमें एसोसिएशन के चेयरमैन शौकत तांबोली, अध्यक्ष रफीक शेख और अब्दुल कादिर खान उपस्थित थे। इस अवसर पर शौकत तांबोली ने बताया कि सऊदी अरब सरकार ने हज 2026 के लिए नियम और समय-सारिणी तय कर दी है, जो विश्व भर के सभी हज यात्रियों पर लागू होगी। इच्छुक हज यात्रियों को

अपनी सीट बुकिंग का पंजीकरण तथा उससे संबंधित सभी प्रक्रियाएं 15 जनवरी 2026 से पहले पूरी करनी होंगी। हज यात्रा 18 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 23 मई 2026 तक चलेगी। 15 जनवरी के बाद किसी भी नए यात्री का पंजीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा, यह स्पष्ट रूप से सऊदी अरब सरकार द्वारा सूचित किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रत्येक हज यात्री की चिकित्सीय जांच अनिवार्य की गई है। इस जांच के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यात्री शारीरिक रूप से हज यात्रा के लिए सक्षम है या नहीं। केवल फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त यात्रियों को ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। ये नियम और शर्तें दुनिया भर के सभी हज यात्रियों पर समान रूप से लागू होंगी। इसके अलावा, 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इस यात्रा में अनुमति नहीं दी जाएगी। हज यात्रियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और समुचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सऊदी अरब सरकार ने ये नियम लागू किए हैं। इसलिए सभी इच्छुक हज यात्री और हज टूर ऑपरेटर्स से अनुरोध किया गया है कि वे इन नियमों का कड़ाई से पालन करें।

नाइजीरियन12.60 लाख की कोकेन के साथ गिरफ्तार

वसई। दिन दिन रात चौगुना की तर्ज पर वसई तालुका में ड्रग्स की तस्करी नाइजीरियन द्वारा धड़ल्ले से किया जा रहा है।इस तरह नालासोपारा पूर्व के प्रगति नगर इलाके में एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी का मामला सामने आया है। तूलिंज पुलिस स्टेशन की डिटेक्शन टीम और एंटी टेररिज्म सेल (एटीसी) की संयुक्त कार्रवाई में एक नाइजीरियन नागरिक को कोकेन ड्रग्स के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।आरोपी के पास से करीब 60 ग्राम कोकेन बरामद हुई है,जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 12 लाख 60 हजार रुपये बताई जा रही है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक अज्ञात विदेशी नागरिक प्रगति नगर इलाके में ड्रग्स की डिलीवरी देने आने वाला है। सूचना के आधार पर तूलिंज पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय जाधव के मार्गदर्शन में एटीसी और डिटेक्शन टीम ने इलाके में सादी वर्दी में जाल बिछाया और संदिग्ध गतिविधि कर रहे व्यक्ति को रोका। पूछताछ और तलाशी के दौरान उसके पास से कोकेन ड्रग्स बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान व (उम्र 37 वर्ष), निवासी नाइजीरिया के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे मौके पर ही हिरासत में ले लिया और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी यह ड्रग्स कहां से लाया था और किन-किन लोगों को इसकी सप्लाई की जानी थी।

नवारंभ का संदेश लेकर नववर्ष द्वार पर खड़ा है। उसका स्वागत हम पूरे उत्साह-उमंग के साथ अवश्य करें। साथ ही आगामी नववर्ष में न केवल अपने जीवन को, अपने से जुड़े लोगों, समाज और पर्यावरण को बेहतर बनाने का संकल्प भी जरूर लें। न केवल संकल्प लें, उसे क्रियान्वित करने के लिए भी समग्र ऊर्जा से सक्रिय रहें। तभी आगामी वर्ष में चहुंओर नवचेतना का संचार होगा।

नववर्ष में हम करें नवचेतना का संचार

आवरण कथा

कुमार राधारमण

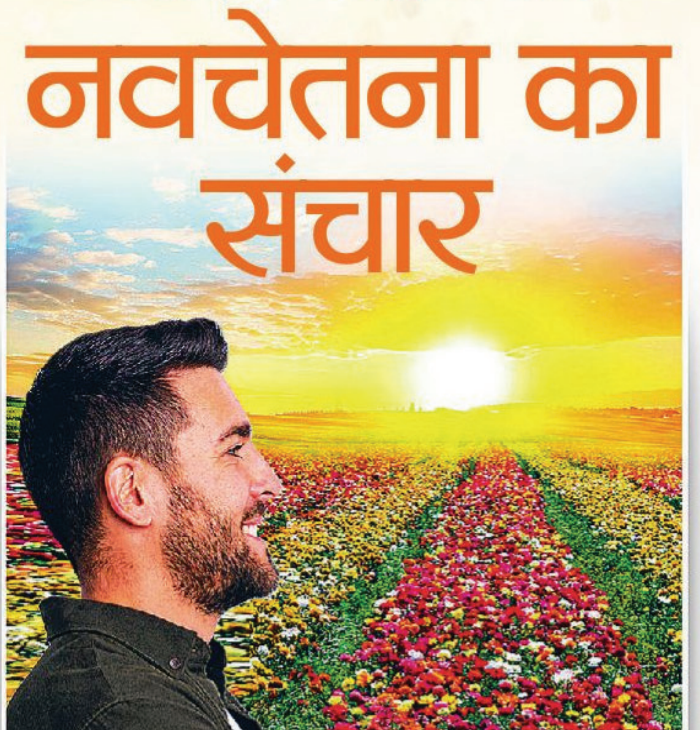

वर्तमान साल बीत रहा है। नए साल ने दस्तक दे दी है। नया साल सिर्फ कैलेंडर का बदल जाना नहीं होता है। यह बीत रहे साल की समीक्षा का अवसर भी है। हम सबकी कुछ अच्छी और कुछ कड़वी यादें इससे जुड़ी होंगी। नया साल विगत की अनुकूल स्मृतियों को सहेजने, उसे नए साल में नई ऊंचाइयां देने का अवसर है। यह प्रतिकूलताओं से सबक लेने का मौका है। जीवन की हर घटना सीखने का अवसर भी होती है। हम सब कई बार चूकते हैं। हमारी चूक निराशा का कारण न बने, हम अपनी गलतियों से सीखें। इसी में वर्तमान का उल्लास भी है और भविष्य का सुनहरा स्वप्न भी।

बनाए रखेंगे सकारात्मक दृष्टिकोण: नया साल, नए उत्साह, नई संभावनाओं, नए सपनों और नए संकल्पों को नए पंख देने का अवसर है। जीवन में हमेशा एक नई शुरुआत संभव है। बीत रहा साल चाहे जैसा रहा हो, नए साल में हम अपनी कहानी फिर से लिख सकते हैं। हर नए दिन का उपयोग हम अपने लक्ष्य के करीब जाने के लिए कर सकते हैं। यह सकारात्मक सोच से ही संभव होगा, क्योंकि चुनौतियों को अवसर में बदलने की क्षमता तभी विकसित होती है। हर समस्या, अपना समाधान भी लिए होती है। इसलिए,

बीता साल जैसा भी रहा, उसे धन्यवाद दें कि हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण प्रसंग उपस्थित हुआ। धन्यवाद इसलिए कि बीते साल की सफलताओं ने हमको आत्मविश्वास दिया, खुशियां दीं और असफलताओं ने हमको मजबूत, संवेदनशील और समझदार बनाया।

प्रकृति नित नूतन है। यह नूतनता पुराने के प्रति आग्रह छोड़ने का निमंत्रण है। विगत चाहे स्वर्णकाल रहा हो, हमारी आज की चुनौतियां नई हैं और हमें आज की परिस्थितियों में निखरने के लिए हमेशा अपने मन के द्वार नए के लिए खुले रखने होंगे। विकास की यही परिभाषा है। सिर्फ व्यापार को ही नहीं, मन को भी मुक्त करने की जरूरत है। सभी समस्याओं की जड़ भूत और भविष्य से बंधा हमारा मन ही है, जबकि चुनौतियां वर्तमान की हैं। मुक्त मन समावेशी तो होता ही है, दूसरों की मुक्ति के द्वार भी खोलता है।

सीखेंगे नित नए कौशल: तेजी से बदलती इस दुनिया में निरंतर सीखना और अपना कौशल विकास करते रहना जरूरी है। व्यस्तता हमें अनचाहे ही अकसर अपने प्रियजनों से दूर कर देती है। वास्तविक दुनिया के लोगों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना भी हमारा संकल्प हो। इससे क्षमाभाव मजबूत होगा, पुरानी कड़वाहट दूर होगी, संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, मन हल्का और खुश रहेगा। अपने लिए यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें। बड़े सपने देखें, बशर्ते उसे कार्यरूप देने का सामर्थ्य भी हम में हो।

तन-मन का रखेंगे ध्यान: स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं। संतुलित आहार और पर्याप्त नींद भी हमारे संकल्प का हिस्सा हो। मौजूदा उन्मादी दौर में मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है। तनाव प्रबंधन सीखना और सकारात्मक मानसिकता विकसित करना आधुनिक जीवन की आवश्यकता है। हर हाल में अच्छाई खोजना और आशावादी रहना जीवन को रूपांतरित कर देता है। हम सक्षम हैं और सफल होने के योग्य हैं, यह विश्वास सदा बना रहे। विंस्टन चर्चिल का प्रसिद्ध कथन है कि न तो सफलता अंतिम होती है, न असफलता घातक होती है, असली बात यह है कि आपमें जारी रखने का साहस है या नहीं।

धनार्जन भी है जरूरी: धन भी महत्वपूर्ण है। गरीब रखने वाली विचारधारा से दूर रहें। वित्तीय लक्ष्य तय करें। बचत और निवेश बुद्धिमत्तापूर्वक करें। अनावश्यक खर्चे कम करना भी धन अर्जित करना ही है। लेकिन भविष्य की सुरक्षा के लिए किए जा रहे प्रयास वर्तमान को जाया न कर दें। भविष्य

अनिश्चितताओं से भरा है। अगली पीढ़ी के लिए सब सोचना आपका ही दायित्व नहीं है, अगली पीढ़ी खुद भी अपने लिए करेगी ही। आप अपने वर्तमान को स्वर्णिम बनाएं। जब आप खूब धन कमा लेंगे, एक दिन वही धन ऊब पैदा करने लगेगा। भौतिक धन परमधन को पाने का साधन मात्र रहे। पावर ऑफ मेनिफेस्टेशन का उपयोग केवल धन को आकर्षित करने के लिए न करें। हमारे पास जो कुछ भी है, उसके प्रति कृतज्ञता से जीवन में अच्छाई को आकर्षित करना भी सीखें।

रहेंगे खुद के करीब: समय धन से भी अधिक कीमती है। इसका सदुपयोग करें। आलस्य छोड़ें, तभी हम अधिक उत्पादक और सफल बन पाएंगे। आलस्य छोड़ने का मतलब हर समय व्यस्त रहना नहीं है। आराम और मनोरंजन भी महत्वपूर्ण हैं। संतुलन चाहिए। आत्म-प्रेम समग्र विकास के लिए जरूरी है। अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए समय निकालना हमारे जीवन को समृद्ध बनाता है। लिहाजा, रोजमर्रा के जीवन में कुछ पल ऐसे जरूर हों, जो नितांत निजी हों, जिसमें मोबाइल की भी दखल न हो। अपने लिए समय निकालना जरूरी है। लेकिन यह औरों के बनाए रील्स देखने के लिए न हो। यह समय अपनी पसंद के काम करने, किताबें पढ़ने, संगीत सुनने, ध्यान करने या प्रकृति से जुड़ने का हो जो हमको तरोताजा कर दे।

समाज-पर्यावरण का रखेंगे ध्यान: सभ्य नागरिक अपने समाज और पर्यावरण के प्रति भी जिम्मेदार होता है। हमारी पृथ्वी रहने लायक बनी रहे, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम आदर्श बनें, नया साल इस संकल्प से भरने का समय भी है। जरूरतमंदों की मदद और सामाजिक कार्यों में भागीदारी आंतरिक संतुष्टि देती है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और नई चीजें आजमाने का साहस रखें। जीवन एक साहसिक यात्रा है और नए अनुभव हमें जीवंत और उत्साहित रखते हैं। सच्ची खुशी और संतुष्टि अनुभव, रिश्ते और भीतरी शांति ही देती है।

शांति के लिए करेंगे प्रयास: इस समय दुनिया भर में राजनीतिक और आर्थिक कारणों से अस्थिरता, अनिश्चितता का माहौल है। भय और चिंता के इस परिदृश्य में, अंतर्मंथन की जितनी जरूरत आज है, पिछले कुछ दशकों में शायद ही रही हो। युद्धों की आहट अनेक आशंकाएं पैदा कर रही हैं। हमारी वास्तविक जरूरत शांति है। शांत मन ही गहरी से गहरी समस्या का सम्यक समाधान तलाश सकता है और एक बेहतर जीवन की ठोस आधारशिला तैयार कर सकता है। विश्व शांति किसी धर्म या हथियार से नहीं, बल्कि जागरूकता से, हृदय से आ सकती है और उसका मार्ग ध्यान है। इसी से मनुष्य, मनुष्य से जुड़ा महसूस करेगा। प्रतिकूल समय में ही ज्ञान, धर्म, साहस और ऊर्जा की परीक्षा होती है। असली ज्ञान, ऊर्जा, धर्म और पराक्रम यह है कि हम जहां भी हों, वहां के आस-पास की प्रकृति कोमल हो जाए। हम जिनके बीच रहें, उनकी भलाई स्वतः प्रकट होने लगे। हमारे भीतर इतनी गहरी शांति उतर आए कि सबके प्रति एक स्वीकार भाव हो। हम इसके लिए अपने स्तर पर अवश्य प्रयास करेंगे, ऐसा संकल्प जरूर लें। तब निश्चय ही आगामी वर्ष खुशहाली से भरपूर होगा। *

विशेष : वैश्विक परिवार दिवस, 1 जनवरी

वर्ष का पहला दिन यानी 1 जनवरी को पूरी दुनिया में ग्लोबल फैमिली-डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य परिवार की महत्ता को समझना और पारिवारिक प्रेम-सौहार्द की भावना को व्यक्तिगत जीवन से लेकर समाज, देश ही नहीं पूरे विश्व में प्रसारित करना है।

व्यक्तिगत से वैश्विक कुटुंब तक बना रहे प्रेम-सौहार्द-शांति

आह्वान / शिखर चंद जैन

हर वर्ष 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली-डे यानी वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर के लोगों को एक बड़े वैश्विक परिवार के रूप में जोड़ने के साथ ही उनमें शांति, एकता, प्रेम और सौहार्द के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है।

भारत की प्राचीन अवधारणा: हमारे देश में तो प्राचीन काल से ही 'वसुधैव कुटुंबकम' की अवधारणा को महत्व दिया जाता रहा है। लेकिन आधुनिक विश्व में ग्लोबल फैमिली-डे मनाने की शुरुआत, संयुक्त राष्ट्र के 'शांति के एक दिन' की विचारधारा से हुई थी। इसे देश, धर्म या नस्ल की सीमाओं से परे सभी लोगों द्वारा मिलकर मनाया जाता है। इस प्रकार यह दिन प्रेम और सद्भाव फैलाने पर जोर देता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हम सब एक वैश्विक गांव के ही सदस्य हैं और हमें सभी मतभेदों को भुलाकर एक परिवार की तरह रहना चाहिए। इसके तहत सभी को प्रेम, शांति और सौहार्द के साथ रहना सिखाया जाता है। दुनिया में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना और युद्ध-हिंसा से बचाना इसका मूल उद्देश्य है।

कब-कैसे हुई शुरुआत: वैश्विक परिवार दिवस मनाने का विचार पिछली सदी में एक किताब से आया था। इसकी शुरुआत 1990 के दशक के अंत में हुई, जब 1997 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2000 को 'शांति की संस्कृति के लिए अंतरराष्ट्रीय दशक और विश्व के बच्चों के लिए अहिंसा' के रूप में घोषित किया। इस अवधारणा को स्टीव डायमंड और एलन सिल्वरस्टीन द्वारा लिखित बच्चों की एक किताब 'वन डे इन पीस, जनवरी 01, 2000' से प्रेरणा मिली। इस कहानी में एक ऐसी दुनिया की कल्पना की गई थी, जहां लोग 1 जनवरी को अपने सभी मतभेदों को एक तरफ रख देते हैं और भाईचारे की भावना का जश्न मनाते हैं। इसने 'शांति का एक दिन' समारोह की शुरुआत की। 1999 में, संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को शांति लाने के लिए वर्ष का पहला दिन समर्पित करने का औपचारिक निमंत्रण मिला। 2001 में, संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर इस दिन को मान्यता दी, और तब से हर साल 1 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है।

मनाती है पूरी दुनिया: वैश्विक परिवार दिवस का उत्सव भौगोलिक सीमाओं से बंधा नहीं है, बल्कि यह एक वैचारिक उत्सव है। इसे किसी एक देश का पर्व मानने के बजाय, मानवता के प्रति एक वैश्विक दृष्टिकोण के रूप में मनाया जाता है। वैश्विक परिवार दिवस सरल, सार्थक कार्यों के बारे में ध्यान आकर्षित करता है, जो घर परिवार से लेकर वैश्विक एकता की भावना को दर्शाता है।

परिवार के संग मनाएं यह दिन: यह दिन संघर्षों को भूलकर, एक-दूसरे के प्रति आभार व्यक्त करने और प्रेम फैलाने पर जोर देता है। इस पूरे दिन आप अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। इसके लिए परिवार के सदस्य एक साथ भोजन कर सकते हैं, कोई सामूहिक खेल, खेल सकते हैं या एक-दूसरे से बात करते हुए अच्छा समय गुजार सकते हैं। आप चाहें तो इस दिन को सामुदायिक सेवा के लिए स्वयंसेवा करके या वैश्विक स्तर पर शांति के लिए काम करने वाली संस्थाओं के लिए श्रमदान करके भी मना सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने ग्लोबल मित्रों की विभिन्न संस्कृतियों, उनकी परंपराओं, व्यंजनों या कहानियों को साझा करके वैश्विक विविधता की भावना को मजबूत किया जा सकता है।

अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस से अलग: हालांकि इस दिन को मनाने की शुरुआत मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई, लेकिन इसे अब दुनिया भर के लगभग हर देश के परिवारों द्वारा मनाया जाता है, जिसमें हर देश और संस्कृति के लोग शामिल होते हैं। इससे मिलता-जुलता एक और महत्वपूर्ण दिवस अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस (इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज) भी है, जो हर साल 15 मई को मनाया जाता है, इसे भी संयुक्त राष्ट्र ने ही घोषित किया था और यह भी परिवार के महत्व पर केंद्रित है। *

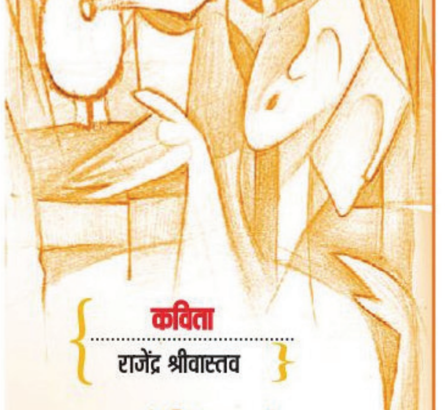

कविता

राजेंद्र श्रीवास्तव

एक वर्ष फिर बीत गया

बीते वर्षों जैसा ही कुछ, एक वर्ष फिर बीत गया।
कभी हृदय खिल उठा पुष्प-सा,
और कभी गुपचुप रोया।
कभी सफलता स्वयं आ गई,
कभी स्वर्ण-अवसर खोया।
आता-जाता रहा वक्त भी
अपने ही रथ पर चढ़कर,
कालचक्र की उथल-पुथल में यह जीवनघट रीत गया।
हर्ष, शोक, संघर्ष, समन्वय,
सुख-दुख, धूप-छांव जैसे।
कुछ दिन बीते खुशहाली में,
बीते कुछ जैसे-तैसे।
दांव-पेंच षडयंत्रों का भी
खेल सीखने विवश हुआ,
जीता कभी किसी से मैं या, कोई मुझसे जीत गया।
जब-जब स्वर गीतों-गजलों के
मेरे होंठों पर आए।
लय तब कहीं अधूरी पाई
वाद्ययंत्र बिगड़े पाए।
हारा नहीं आत्मबल लेकिन
कोई जतन सफल होगा,
बिगड़े साजों से रच दूंगा, मैं कोई संगीत नया।

व्यंग्य / अंशुमाली रस्तोगी

ठंड में चोरी करना आसान काम नहीं। जब लोग अपनी-अपनी रजाइयों में छिपे-दुबके बैठे होते हैं, तब चोर उनके घरों में चोरी करने उतरते हैं। एक तरफ ठंड का सितम, दूसरी तरफ पकड़े जाने का डर। फिर भी, वे अपने कर्म पथ पर डटे रहते हैं।

ठंड और चोर

इन दिनों ठंड आतंक मचाए हुए है। रजाई से बाहर निकलने का मन नहीं करता। न नहाने का दिल करता है। जी करता है, पूरे टाइम रजाई में सिकुड़े पड़े रहो। लेकिन मैं दाद देता हूं उन चोरों को, जो भीषण ठंड में भी चोरी कर रहे हैं। ठंड में चोरी करना आसान काम नहीं। जब लोग अपनी-अपनी रजाइयों में छिपे-दुबके बैठे होते हैं, तब चोर उनके घरों में चोरी करने उतरते हैं। एक तरफ ठंड का सितम, दूसरी तरफ पकड़े जाने का डर। फिर भी, वे अपने कर्म पथ पर डटे रहते हैं। पापी पेट क्या-क्या नहीं करवा लेता। आज के जमाने में चोरी करना पाप कैसे कहा जा सकता है!

बदलते समय के साथ चोरी के तरीके भी काफी बदल गए हैं। कुछ चोरियां अब ऐसी भी हैं, जिनके लिए घर से बाहर निकलना ही नहीं पड़ता। वे घर बैठे-बैठे ही हो जाती हैं। ऑनलाइन ठगी (चोरी) में कहीं जाने की जरूरत नहीं। कहीं से भी बैठकर किसी के भी बैंक खाते से रुपए उड़ाए जा सकते हैं। ये चोर बेहद शातिर होते हैं। बातें बनाकर फंसाने में माहिर होते हैं। इधर सावधानी घटी, उधर काम तमाम हुआ। लेकिन ऑनलाइन चोर पारंपरिक चोरों की तरह मेहनती नहीं होते। माना कि ऑनलाइन चोरी में मुनाफा अधिक है किंतु जमीनी अनुभव न के बराबर है। ऐसी चोरी भला किस काम की, जिसमें हाथ-पैर न हिलाने पड़ें।

अब तो पारंपरिक चोरों ने भी ऑनलाइन चोरी का रास्ता पकड़ लिया है। वे भी अधिक मेहनत करने से कतराने लगे हैं। चोरी की लाइन में नई पीढ़ी जो आ रही है, उसका झुकाव ऑनलाइन ठगी की तरफ ज्यादा है। चोरी के नए-नए तरीके उसने ईजाद कर लिए हैं। फोन पर लोगों को उल्लू बनाकर खाते से पलभर में रुपया सफा-चट कर रहे हैं।

लेकिन मुझे तो जमीन से जुड़े पारंपरिक चोर ही अधिक पसंद हैं। वे चोरी करते हैं तो लगता है कि वास्तविक चोरी हुई है। चोरी की रपट लिखी जाती है। पुलिस मौका-ए-वारदात पर पहुंचती है। चोरी गई चीजों का हिसाब-किताब लगाया जाता है। ध्यान रहे, चोरी में गहने जरूर चुरते हैं। नकदी पर भी हाथ साफ किया जाता है। घर वालों, आस-पड़ोस, नौकर-चाकर से पूछताछ होती है। खबर अखबारों में छपती है। चार जन चाय और पान के खोके पर चर्चा करते हैं। मोहल्ले में दहशत का सा माहौल बनता है। चोरी होने वाले घर का दूर-दूर तक नाम होता है। कुछ भी कहिए, सीन पारंपरिक चोरी में ही बनता है।

विकट ठंड में चोरी कंपकंपी छुड़ा देती है। मगर पापी पेट की खातिर उन्हें यह करना पड़ता है। आखिर उनका भी परिवार है। उन्हें भी अपने शौक पूरे करने हैं। बीवी की पसंद और बच्चों की पढ़ाई-लिखाई का भी ध्यान रखना है। चोरों का भी दिल होता है। मैंने कहानियों में कई ऐसे चोरों के बारे में सुन रखा है, जो चोरी की कमाई गरीबों में बांट दिया करते थे। कभी निम्न वर्ग को परेशान नहीं करते थे। उनके टारगेट पर हमेशा धन्नासेठ ही रहा करते थे। कितने दयावान चोर थे वे। मेरा मानना है कि चोरी करना, कविता या व्यंग्य लिखने से कहीं कठिन काम है। जितनी अक्ल चोरी करने में लगानी पड़ती है न, उतनी गणित के सवाल हल करने में नहीं। लेकिन लोग हैं कि चोरों को हमेशा बद-दुआएं देते हैं। कभी उनका आदर-सम्मान नहीं करते। चोर हैं तो क्या, इंसान तो वे भी हैं। इतना तय है कि धरती से जैसे भ्रष्टाचार कभी नहीं मिट सकता, वैसे ही चोरी भी कभी खत्म नहीं हो सकती। चोरों में भी नई-नई नस्लें आती रहेंगी। नए-नए तरीके चोरी के ईजाद किए जाते रहेंगे परंतु चोरियां खत्म कभी न होंगी। ठंड के मौसम में चोरी करना निश्चित ही कर्रा काम है। मेरे विचार में ऐसे वीर चोरों को कोई न कोई पुरस्कार भी जरूर मिलना चाहिए! नहीं क्या...! *

ये किनकी सांसों के सौदे

लड़ाई के योद्धा न डाक्टरों की हड़ताल और न ही किसी डाक्टर की बर्खास्तगी से तय हुए, मगर पूरे प्रदेश की पूरी-पूरी जनता आहत हुई हर बार। इस बीमारी के लक्षण केवल आईजीएमसी में ही मिले हों, सही नहीं होगा। बीमारी के लक्षण सरकारी इलाज के तरीकों या सरकार के फायदों को भुनाती जनता में ही हैं। हम काबिल डाक्टर की खोज में बीमार होते हैं या मरीजों की शुमारी में खुद डाक्टर परेशान होते हैं। परेशानियों का सबब यह कि अस्पतालों की गुंडई में जोर जबरदस्ती का नारा है। करीब तीन हजार सरकारी डाक्टर इसलिए अस्पतालों से गैर हाजिर हैं, क्योंकि उनके सहयोगी डाक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है। यह किस्सा इतना भी नर्म नहीं है कि सरकार सख्त न होती और इतना भी स्वाभाविक नहीं कि किसी एक पक्ष को कमजोर आंक लें। ताकत डाक्टरी पेशे ने उस वक्त दिखाई होगी, जब एक मरीज को दुश्मन माना गया होगा। जब अस्पताल की चटाई या बिस्तर की लंबाई में मरीज छोटा हो जाए, तो डाक्टरी का प्रोफेशन खुदा से भी ऊपर अपनी ताकत बताता है। इसी ताकत के आगे आए दिन मेडिकल कालेजों तक में व्यवस्था हारती है, लेकिन डाक्टर एक कैबिन है-पिंजरा नहीं। उसकी क्षमता और दक्षता में अंतर है। यही अंतर चिकित्सा सेवाओं का अंतर्विरोध बन जाता है। फर्ज के लिखित संदेश व्यावहारिक नहीं होते, क्योंकि दुनिया बीमार है। हमने डिस्पेंसरी छोड़ी, ताकि सिविल अस्पताल बेहतर साबित हो। नागरिक अस्पताल छोड़ा ताकि जोनल या क्षेत्रीय अस्पताल में दक्षता मिल जाए और अब सारा हिमाचल गिन रहा है मेडिकल कालेज। शायद इसीलिए आईजीएमसी के बिस्तर पर लेटा मरीज अपने जीने के अरमानों को मेडिकल कालेज के दर पर ले आया था। इसमें दो राय नहीं कि मरीज का आचरण आक्रोश नहीं, लेकिन हर मरीज बेहोश नहीं होता। मामला डाक्टर और मरीज बन जाए, तो इस जीत-हार में सिर्फ विश्वास हारता है।

डाक्टर मरीजों पर नजर रखेंगे कि कहीं कोई बिगड़ा मरीज या उसका तीमारदार न निकल आए और मरीज डरेगा कि कहीं डाक्टर का हाथ न उठ जाए। यह भी एक विडंबना है कि पहले डाक्टर अपने तौर पर मरीज का मनोविज्ञान और चिकित्सा विज्ञान हाथ से टटोलते थे, लेकिन अब बीमारी की सारी अर्जियां इतनी मेहनत कराती हैं कि चिकित्सा पद्धति, यातना की मजदूर बना देती है। आईजीएमसी के घटनाक्रम में न तो मरीज याचक था और न ही डाक्टर शरीफ था। जो अस्पताल परिसर में घूंसे चला सकता है, उसे रिंग में होना चाहिए और जिस मरीज की जुबान कर्कश हो, उसे सुधारने की जरूरत है। क्या वक्त आ गया है जब डाक्टरों को मार्शल मिलने चाहिए या मरीजों के साथ पुलिस के सिपाही चलने चाहिएं। ऐसे में सरकार की नर्म कर्मचारी नीतियां दोषी हैं या प्रदेश में प्रोफेशनलिज्म अभी आया ही नहीं। कल अगर ट्रैफिक नियंत्रित करने वाले सिपाहियों को वाहन चालक सरेआम पीटना शुरू कर दें या प्रशासन के आदेशों के खिलाफ मुहिम खूंखार होने लगे, तो सरकार कैसे फैसले लेगी। इसके विपरीत अगर हर विभाग और विभागीय ओहदे आम जनता के प्रति आक्रामक हो जाएं, तो तब सरकार क्या करेगी। यह एक अवांछित छूट का अधिकार है, जो सरकारें कर्मचारियों और अधिकारियों को सिर पर बैठा कर व्यवस्था को पुचकारती रही हैं। इस प्रदेश में पनपते हर जोखिम के छोर पर जनता की मजबूरियां बैठी हैं। प्रदेश कितना शक्तिशाली या व्यवस्था पसंद है, उसकी हवा डाक्टर निकाल चुके हैं। अगर तीन हजार डाक्टर तमाम सरकारी अस्पतालों का भट्ठा बिठा सकते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में स्कूल-कालेजों और कानून व्यवस्था का क्या होगा। कितने दर्द में तेरे एहसास घायल कर गए, ये सिर्फ तेरी बगावत नहीं शेखियां ही थीं। एक दिन के लिए किसी मेडिकल कालेज के आपरेशन थियेटर का बंद होना, कितनी सांसों का सौदा है। मरीजों की कतारों में बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, अपाहिज और असहाय भी होंगे, मगर डाक्टरों की बादशाहत में अस्पताल लुट गया। सजा किसे मिली। डाक्टर या मरीज को या उस व्यवस्था को जिसके भरोसे जनता सांस लेना चाहती है। ऐसे में जनता के अविश्वास से सरकार के प्रयास हर सरकारी अस्पताल में फेल होंगे, क्योंकि तालेबंदी जैसी स्थिति में डाक्टर ही पेशे के हुक्मरान हैं। फिर न कहना कि हिमाचल में निजी अस्पताल लूट रहे हैं।

युंका एवं एनएसयूआई ने फूंका बांग्लादेश के पीएम का पुतला

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक एवं हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में सोमवार को यहां अग्रसेन चौक पर युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेन्द्र यादव एवं एनएसयूआई जिलाध्यक्ष आकाश साहू के नेतृत्व में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया।मामले में विदेश नीति पर मोदी सरकार की विफलता को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। युवा कांग्रेस एवं एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विश्रामगृह से पदयात्रा करते हुए अग्रसेन चौक में पुतला दहन किया। साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बताया गया कि बांग्लादेश में लगातार हिन्दुओं एवं अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे है एवं उनकी हत्या की जा रही है बांग्लादेश के साथ-साथ अन्य देशों में भी लगातार हिन्दू विरोधी घटनाएं हो रहे है और इस पर प्रधानमंत्री की चुप्पी समझ नहीं आ रही है बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन जमाती इस्लामी पर रोक के मामले हो या अन्य हिन्दू विरोधी मामले में भारत सरकार का विदेश विभाग एवं खुफिया तंत्र अनुमान लगाने में विफल साबित हो रहा है। बताया गया कि लगातार हो रहे घटनाएं चिंताजनक है धर्म एवं राजनीति के आधार पर दुनिया के किसी भी हिस्से में हिंसा अस्वीकार है ऐसी घटनाएं होने के बाद भी भारत सरकार बांग्लादेश को मजबूत संदेश देने में विफल रही है कार्यकर्ताओं ने पत्र के माध्यम से सरकार को इस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी के तरह दृढ़ता दिखलाते हुए स्पष्ट सैद्धांतिक प्रतिक्रिया देने का कदम उठाने की मांग की गई है और बताया गया कि सरकार अगर ठोस कदम उठाती है तो कांग्रेस पार्टी साथ देगी।

प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

इस दौरान पुर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष भगवती राजवाड़े, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष नरेश राजवाड़े, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष राजीव सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष कुसुमलता राजवाड़े, मनोज अग्रवाल, हेमेंद्र गुप्ता, नीरज तायल, विष्णु कसेरा, अविनाश यादव, नैतिक अग्रवाल, अनुराग डालमिया, सूरज गुप्ता, सूरज अवस्थी, बंटी सिंह, मोहसिन रजा, प्रशांत साहू, लिवनेश सिंह, राजेश साहू, रूद्र प्रताप सिंह, शाहरुख खान, युवध सिंह, मधु साहू, दिलीप सोनी, लक्ष्मण राजवाड़े, हरी साहू, नितेश साहू, शिवम साहू, हैदर अली, आशीष साहू, यश दास, पीयूष कुशवाहा, कलकत्ता राजवाड़े, सोमु खान, अजय सिंह, उत्तम यादव, अखिलेश सिंह, सावित्री शर्मा, संगीता राजवाड़े, तनवीर, राम सिंह, त्रिलोचन प्रसाद, अज्जू अंसारी, तनवीर, आशीष सिंह, वारिश खान, कृष्णा तिवारी, दया राजवाड़े, भोला प्रसाद राजवाड़े, अमोली नंद, कृष्ण बिहारी साहू, शिव राजवाड़े, देव राजवाड़े, हरवंश राजवाड़े, धर्मेन्द्र साहू, पुनीत विश्वकर्मा, विनय चौधरी, बाबू दुबे, मोना खान, रामचन्द्र राजवाड़े, अदनान सिद्दीकी, शनि जायसवाल, सुमंत राजवाड़े, विवेक सिंह, विनय पावले, विकास गुप्ता, घनश्याम, प्रकाश, श्रवण कुमार, रवि महंत, सुमीत, विनय दुबे सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।

न्यायालय अपर कलेक्टर एवं प्राधिकृत अधिकारी (भू-अर्जन)

जिला -मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.)

फोन: - 07771-299057 ई-मेल : -collector-mcb@cg.gov.in

क्रमांक/7689/न्याया. अपर कले./भू-अर्जन/2025 मनेन्द्रगढ़ दिनांक 24.12.2025

// रेल अधिनियम, 1989 की धारा- 20 च(4) के अंतर्गत//

//संशोधित लोक-सूचना//

विषय:- प्रस्तावित रेलवे परियोजना हेतु भूमि/संरचना के अधिग्रहण के पूर्व प्रतिकर राशि के निर्धारण एवं आपत्तियों हेतु लोकसूचना।

यह विदित हो, कि रेल अधिनियम, 1989 के अंतर्गत **चिरमिरी-नागपुर हॉल्ट नई ब्राड गेज रेल्वे लाईन छत्तीसगढ़ रेलवे परियोजना** के निर्माण हेतु निम्नलिखित ग्रामों की भूमि/संरचनाओं को अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित किया गया है।

उक्त अधिग्रहण हेतु प्राथमिक प्रतिकर राशि (Provisional Compensation) की गणना की जा रही है। इस संबंध में निम्न विवरण प्रस्तुत है—

1. प्रस्तावित अधिग्रहित भूमि/संरचना का विवरण-

क्रमांक	अधिग्रहण का विवरण	
1	ग्राम/नगर	सरोला
2	तहसील	मनेन्द्रगढ़
3	जिला	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
4	खसरा/प्लॉट नंबर एवं अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल	(नीचे तालिका अनुसार)
5	भूमि का प्रकार : - कृषि योग्य/अकृषि/आवासीय/ व्यावसायिक आदि	प्रपत्र – क अनुसार
6	स्वामी/दावेदार का नाम	प्रपत्र – क अनुसार

क्र.	खसरा नं.	रकबा
1	111	0.160
2	108/1	0.180
3	113/2	0.030
4	113/3	0.056
5	113/5	0.010
6	113/6	0.040
	कुल खसरे – 06	कुल रकबा – 0.476 हे.

प्रतिकर राशि निर्धारण हेतु आधार -

क्रमांक	अधिग्रहण भूमि के प्रतिकर राशि का विवरण	
1	छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य निर्धारण संबंधी उपबंध 2025-26 का एवं वर्तमान वर्तमान बाज़ार मूल्य।	प्रपत्र – क अनुसार
2	भूमि का उपयोग/प्रकृति	प्रपत्र – क अनुसार
3	संरचना/फसल/वृक्षों का मूल्यांकन	प्रपत्र – ख अनुसार
4	रेलवे परियोजना से प्रभावित अन्य परिसंपत्तियों का मूल्य	प्रपत्र – क अनुसार
5	अधिनियम/नियमों के अनुसार देय अन्य लाभ	प्रपत्र – क अनुसार

3. आपत्ति/दावा प्रस्तुत करने की सूचना -

उक्त प्राथमिक प्रतिकर गणना के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को भूमि स्वामित्व, क्षेत्रफल, वर्गीकरण, मूल्यांकन एवं प्रतिकर राशि के संबंध में कोई **आपत्ति, दावा या अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहते हों**, तो स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से निम्नलिखित अवधि एवं स्थान पर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें -

- आपत्ति ग्राह्य करने की अवधि तिथि :- 12/01/2026 से 02/02/2026 तक **(अवकाश दिवस-प्रत्येक शनिवार, रविवार तथा दिनांक 26/01/2026 एवं अन्य घोषित शासकीय अवकाश को छोड़कर)**
- प्रस्तुति का स्थान :- न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, छत्तीसगढ़ (कक्ष क्र. - 08)
- समय :- प्रातः 12:00 से दोपहर 03:00 बजे तक

4. महत्वपूर्ण सूचना

1. नियत समय के भीतर प्राप्त दावों/आपत्तियों पर विचार किया जाएगा।
2. उचित प्रक्रिया पश्चात **प्रतिकर राशि का अंतिम अवॉर्ड** पारित किया जाएगा।
3. प्रभावित भू-स्वामियों को सुनवाई हेतु पृथक से सूचना जारी की जावेगी।

5. संपर्क अधिकारी

नाम : श्री अनिल कुमार सिदार
पद : अपर कलेक्टर एवं प्राधिकृत अधिकारी
कार्यालय : कलेक्टर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.)
फोन : 07771-299057
ई-मेल : collector-mcb@cg.gov.in

मुहर

(अनिल कुमार सिदार)
अपर कलेक्टर एवं प्राधिकृत अधिकारी (भू-अर्जन)
चिरमिरी-नागपुर हॉल्ट नई ब्राड गेज
रेल्वे लाईन छत्तीसगढ़ रेलवे परियोजना
जिला: मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.)

मुआवजा गणक पत्रक – क

ग्राम– सरोला तहसील– मनेन्द्रगढ जिला– मनेन्द्रगढ–चिरमिरी–भरतपुर (छ०ग०)

1	हितबध्द व्यक्ति/भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	अर्जित भूमि का क्षेत्रफल (रकबा हेक्टे. में)	प्रचलित गाईड लाईन के अनुसार बाजार मूल्य प्रति हे० की दर से (राशि रु. में): मुख्य मार्ग से पर स्थित भूमि	सिंचित भूमि	असिंचित भूमि (सिंचित भूमि का 80 प्रतिशत)	अर्जित भूमि का मूल्यांकन (प्रतिकर की राशि रूपये में)	भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र का गुणांक (2.0) (बाजार मूल्य सहित)	परिसम्पत्तियों के प्रतिकर का विवरण (राशि रूपये में): वृक्ष	भवन/ बाउंड्रीवाल	कूप/ कुआं	नल कूप	योग स्तम्भ (10)+(11)+(12)+(13)	प्रतिकर की कुल राशि (9+14) में	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–105 के संशोधन क धारा 30(1)के अन्तर्गत 100 प्रतिशत अतिरिक्त तोषण राशि	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–105 के संशोधन की धारा–30(3) के अन्तर्गत 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह की अतिरिक्त धन राशि (कॉलम 08x12x8/12x100)	प्रतिकर की कुल देय राशि पूर्णांक में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	शांति बाई बेवा सुन्दरसाय, सुखदेवलाल, मुन्नीलाल, प्रेमवती आ० सुन्दरसाय, छबीलाल आ० शीतल, फुलेश्वरी बेवा परसराम, राजेश कुमार यादव आ० परसराम इन्दकुमारी, चक्रवती पुत्री पारसराम, बसंत पिता शीतल,	111	0.160	1558000.00	1085000.00	868000.00	249280.00	498560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498560.00	498560.00	19942.40	1017062
2	सुभाषचन्द पिता गोकुल, रामप्रताप आ० भगवान दास,	108/1	0.180	1558000.00	1085000.00	868000.00	280440.00	560880.00	36680.00	0.00	0.00	0.00	36680.00	597560.00	597560.00	22435.20	1217555
3	आलोक कुमार राय पिता उमाशंकर	113/2	0.030	1558000.00	1085000.00	868000.00	46740.00	93480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93480.00	93480.00	3739.20	
4	आशिष कुमार राय पिता उमाशंकर	113/3	0.056	1558000.00	1085000.00	868000.00	87248.00	174496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174496.00	174496.00	6979.84	355972
5	देवकीनंदनी पति आलोक कुमार राय	113/5	0.010	1558000.00	1085000.00	868000.00	15580.00	31160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31160.00	31160.00	1246.40	63566
6	तोशिबाराय पति आशीष कुमार राय	113/6	0.040	1558000.00	1085000.00	868000.00	62320.00	124640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124640.00	124640.00	4985.60	254266
	योग :-		0.476		65,10,000.00	52,08,000.00	7,41,688.00	14,83,216.00	36,680.00	-	-	-	36,680.00	15,19,896.00	15,19,896.00	59,328.64	29,08,421.44

परिसम्पतियो का गणना पत्रक– ख

ग्राम– सरोला तहसील– मनेन्द्रगढ जिला– एमसीबी (छ०ग०)

क.	हितबध्द व्यक्ति/भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	अर्जित भूमि का क्षेत्रफल (रकबा)	परिसम्पतियों का विवरण	परिसम्पतियों की संख्या	परिसम्पतियों का माप (मीटर में)	परिसम्पतियों का क्षेत्रफल (वर्ग मी./से. मी.)	दर	परिसम्पतियों का मुआवजा राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सुभाषचन्द पिता गोकुल, रामप्रताप आ० भगवान दास,	108/1	0.180	साल का पेड	1	-	-	36680.00	36680.00
	योग								36680.00

परिसम्पतियो का गणना पत्रक – ग

ग्राम– सरोला तहसील– मनेन्द्रगढ जिला– एमसीबी (छ०ग०)

क.	हितबध्द व्यक्ति/भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	अर्जित भूमि का क्षेत्रफल (रकबा)	परिसम्पतियों का विवरण	परिसम्पतियों का मुआवजा राशि
1	2	3	4	5	6
1	कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोकस्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड मनेन्द्रगढ़, जिला एमसीबी	115	-	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का पाईप लाईन कनेक्शन	1075000.00
	योग				10,75,000

अपर कलेक्टर
एवं प्राधिकृत अधिकारी (भू-अर्जन)
चिरमिरी-नागपुर हॉल्ट नई ब्राड गेज
रेल्वे लाईन छत्तीसगढ़ रेलवे परियोजना
जिला: मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.)

संवाद-46373/2

कलेक्टर ने धान खरीदी केंद्रों का किया निरीक्षण

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। सोमवार को कलेक्टर एस. जयवर्धन द्वारा जिले के बतरा, सलका, करौटी 'ब' एवं चंद्रमेढ़ा स्थित धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया गया।निरीक्षण के दौरान उन्होंने खरीदी केंद्रों पर उपस्थित किसानों से सीधे संवाद कर धान खरीदी की व्यवस्था, सुविधा एवं प्रक्रिया की जानकारी ली। कलेक्टर ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सभी धान खरीदी केंद्रों में आवश्यक मूलभूत सुविधाएं, सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी खरीदी व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित जिम्मेदारों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा किसानों के हित में धान खरीदी कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु लगातार निगरानी एवं निरीक्षण किया जा रहा है।

जिले की समितियों में अब तक 2.82 लाख क्विंटल धान की गई खरीदी

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिले के खरीदी केंद्रों में धान खरीदी का कार्य सुचारु रूप से संचालित किया जा रहा है। शासन द्वारा किसानों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी, सुव्यवस्थित एवं समयबद्ध बनाया गया है।जिले में अब तक कुल 2,82,226.08 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। इसके लिए समितियों द्वारा 24704 टोकन जारी किए गए हैं, जिनमें से 12,520 टोकन मोबाइल ऐप के माध्यम से जारी किए गए हैं। वहीं, जिले में 7173 किसानों द्वारा 273.015 हेक्टेयर रकबा का समर्पण किया गया है। उल्लेखनीय है कि धान खरीदी प्रक्रिया के दौरान जिला प्रशासन द्वारा अवैध धान भंडारण, खरीदी एवं परिवहन के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। अब तक 61 प्रकरणों में 4550.90 क्विंटल धान जप्त किया जा चुका है। साथ ही कलेक्टर के निर्देशन में जिले की सभी सीमाओं एवं चेक पोस्टों पर अवैध धान भंडारण एवं परिवहन को रोकने के लिए 24 घंटे सतत निगरानी की जा रही है। संदिग्ध वाहनों की सघन जांच के साथ-साथ रात्रिकालीन गश्त भी की जा रही है। आंतरिक चेक पोस्टों पर विशेष टीमों की तैनाती की गई है। इसके अलावा जिले में कोचियों एवं बिचौलियों के माध्यम से अवैध रूप से धान खपाने पर रोक लगाने तथा धान खरीदी प्रक्रिया की प्रभावी निगरानी हेतु जिले में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से खरीदी, भंडारण एवं परिवहन की रियल टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा अवैध धान, कोचियों एवं बिचौलियों से संबंधित शिकायत दर्ज कराने हेतु खाद्य विभाग कॉल सेंटर नंबर जारी किए गए हैं।

संपर्क करें
समाचार, ईश्तहार, विज्ञापन हेतु संपर्क करें।
दैनिक छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन
गौरव पथ, गुरुद्वारा के पास बाबूपारा अम्बिकापुर
मो. 7566950555 9713108088

सरगुजा फ्रंटलाइन

हड़ताल से दफ्तर रहे वीरान, कर्मचारियों ने कहा-मांगों को अनदेखा करना सरकार को पड़ सकता है भारी

फेडरेशन ने 11 सूत्रीय मांगों व मोदी की गारंटी लागू करने हल्ला बोला, 3 दिवसीय कलम बंद-काम बंद आंदोलन शुरू

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा डीए, वेतन विसंगति, कैशलेस उपचार सुविधा सहित 11 सूत्रीय लंबित मांगों व मोदी की गारंटी लागू करो अभियान के तहत सोमवार से तीन दिवसीय कलम बंद, काम बंद आंदोलन शुरू कर दिया है। पहले ही दिन अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा कार्यालयों में काम बंद करके धरना देते हुए सरकार से मांगों को पूरा करने को लेकर नारेबाजी की। फेडरेशन द्वारा इन मांगों को लेकर लम्बे समय से आंदोलन किया जा रहा है। पूर्व में भी संगठन द्वारा हड़ताल किया गया था परन्तु शासन द्वारा दिए गए आश्वासन पर हड़ताल समाप्त किया गया था। एक बार फिर से फेडरेशन ने आंदोलन का आगाज किया है। इस बार 29 से 31 दिसम्बर तक तीन दिवसीय हड़ताल पर अधिकारी-कर्मचारी चले गए

हैं, जिससे कार्यालयीन कार्य बाधित हो रहा है।

फेडरेशन की 11 सूत्रीय मांगों में केंद्र सरकार के समान कर्मचारियों एवं पेंशनरों को देय तिथि से महंगाई भत्ता लागू करना, डीए एरियर्स की राशि कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में समायोजित करना, सभी कर्मचारियों को चार स्तरीय समयमान वेतनमान, लिपिकों, शिक्षकों, स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग सहित विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करना, प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए संपूर्ण सेवा लाभ देना, पंचायत सचिवों का शासकीयकरण, सहायक शिक्षकों एवं सहायक पशु चिकित्सा अधिकारियों को तृतीय समयमान वेतनमान, नगरीय निकाय के कर्मचारियों को नियमित मासिक वेतन एवं समयबद्ध पदोन्नति, अनुकंपा नियुक्ति नियमों में 10 प्रतिशत सीलिंग में शिथिलीकरण, प्रदेश में कैशलेश सुविधा लागू करना, अर्जित अवकाश नगदीकरण 300 दिवस करना, दैनिक, अनियमित, संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की ठोस नीति बनाने व सभी विभागों में समानता लाते हुए सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष करना शामिल है। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव के समय भाजपा द्वारा घोषित मोदी की गारंटी को भी लागू करने की मांग की गई है। इन मांगों को लेकर फेडरेशन द्वारा चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। पूर्व में ज्ञापन व रैली के माध्यम से मांगों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया था, इसके बाद भी मांगों पर सरकार द्वारा कोई ठोस पहल नहीं करने पर अब फेडरेशन द्वारा आंदोलन के तीसरे चरण में तीन दिवसीय हड़ताल शुरू किया गया है। हड़ताल के कारण कलेक्ट्रेट के कार्यालयों में काफी कम कर्मचारी नजर आए। ज्यादातर कर्मचारियों ने हड़ताल में शामिल होकर एसबीआई के कलेक्ट्रेट ब्रांच के पास धरना दिया, जिससे कार्यालयों में कामकाज प्रभावित हुआ। धरना दे रहे अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी भी की गई। इनका कहना था कि सरकार द्वारा मुफ्त में लोगों को पैसा बांटा जा रहा है, परन्तु कर्मचारियों की जायज मांगों को पूरा करने के लिए सरकार के पास पैसों की कमी हो जाती है। फेडरेशन के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश में 4 लाख 30 हजार अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत हैं। इतनी संख्या में कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा करना सरकार को भारी पड़ सकता है। संगठन द्वारा तीन दिवसीय हड़ताल के बाद भी सरकार द्वारा सकरात्मक पहल नहीं करने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। हड़ताल व धरना प्रदर्शन में काफी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी शामिल थे।

समन्वय बनाकर पोषण पुनर्वास केंद्रों में गंभीर कुपोषित बच्चों को भेजें

कलेक्टर की अध्यक्षता में साप्ताहिक समय सीमा की बैठक सम्पन्न

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। कलेक्टर अजीत वसंत की अध्यक्षता में सोमवार को साप्ताहिक समय सीमा की बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टरेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में उन्होंने शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तार से समीक्षा की और प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत सभी प्रकरण तय समय सीमा में पूर्ण करने अधिकारियों को निर्देशित किया। वहीं लंबित राजस्व प्रकरणों को भी गंभीरता के साथ समय सीमा में निराकरण किए जाने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर सुनील नायक, राम सिंह ठाकुर, अमृत लाल ध्रुव, नगर निगम कमिश्नर डीएन कश्यप एवं विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग को आपसी समन्वय के साथ पोषण पुनर्वास केंद्रों में गंभीर कुपोषित बच्चों को सतत रूप से भेजने निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि एनआरसी में शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करें, प्रतिदिन की रिपोर्ट तैयार कर उपलब्ध कराएं। कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को कहा कि जिले के खनन प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं सब हेल्थ सेंटरों में रिक्त पदों की सूची तैयार कर उपलब्ध कराएं। बैठक में उन्होंने अपार आईडी में एंट्री की समीक्षा करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को शत-प्रतिशत बच्चों की एंट्री सुनिश्चित करने निर्देशित किया तथा जन्म प्रमाण पत्र निर्माण हेतु बच्चों की सूची एसडीएम को उपलब्ध कराने कहा। इसी प्रकार उन्होंने कक्षा पहली से 12वीं तक के ऐसे बच्चे जिनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है, उनकी जानकारी भी उपलब्ध कराने कहा।

धान खरीदी की हुई समीक्षा

समर्थन मूल्य पर जिले में जारी धान खरीदी की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने कहा कि टोकन सत्यापन में तेजी लाएं, मुख्य रूप से लघु सीमांत किसानों पर फोकस करें, शत-प्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कोचियो-बिचौलियों पर कड़ी निगरानी रखें, अवैध धान भंडारण पर सख्ती से कार्रवाई हो। उन्होंने जिले में अब तक कि गई खरीदी, खरीदी केंद्रों में किसानों हेतु व्यवस्था एवं सुविधाओं सहित अन्य बिंदुओं पर अनुभागवार समीक्षा की। उन्होंने धान उठाव एवं रकबा समर्पण बढ़ाने निर्देशित किया।

पीवीटीजी युवाओं को रोजगार से जोड़ने की पहल

कलेक्टर ने पीवीटीजी युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त को निर्देशित किया कि जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति के शिक्षित युवाओं की सूची तैयार करें। इनकी कॉलउन्सिलिंग आयोजित कर योग्य युवाओं की फाइनल लिस्ट तैयार करें, ताकि योग्यतानुसार उन्हें विभिन्न विभागों में रोजगार उपलब्ध कराया जा सके।

विधायक के कथित फर्जी जाति प्रमाण पत्र सत्यापन प्रक्रिया की सुनवाई एक बार फिर टली

कर्मचारियों की हड़ताल बनी बाधा, अब निगाहें अगली सुनवाई तिथि पर टिकी

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। प्रतापपुर विधायक शकुंतला पोर्ते के कथित फर्जी जाति प्रमाणपत्र सत्यापन की चल रही प्रक्रिया एक बार फिर कर्मचारियों की हड़ताल के कारण टल गई, और जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति ने सुनवाई स्थगित किया। सुनवाई की अगली तिथि 29 जनवरी निर्धारित की गई है। सोमवार को होने वाली जाति प्रमाण पत्र की सुनवाई को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से चाक-चौबंद व्यवस्था की गई थी। जगह-जगह पुलिस बल तैयनात किया गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर 29 से 31 दिसंबर तक जिले के अधिकारी एवं कर्मचारी हड़ताल पर हैं, हड़ताल का असर जिले के प्रशासनिक कार्यों पर स्पष्ट रूप से देखने को मिला। इसी हड़ताल के कारण 29 दिसंबर को होने वाली जिला स्तरीय जाति प्रमाणपत्र सत्यापन समिति की सुनवाई को स्थगित कर दिया गया। प्रशासन द्वारा जारी आवश्यक सूचना के अनुसार अब यह सुनवाई नए वर्ष में 29 जनवरी 2026 को निर्धारित की गई है। आदेश जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति के अध्यक्ष के निर्देशानुसार जारी किया गया

है। ऐसे में इस मामले में अगली तिथि पर ही विचार किया जाएगा। हड़ताल के चलते जाति प्रमाण पत्र सत्यापन जैसे महत्वपूर्ण मामलों में भी देरी हो रही है।

आपत्ति पर होना था तर्क-अधिवक्ता बृजेंद्र पाठक

विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते की ओर से पहुंचे अधिवक्ता बृजेंद्र पाठक ने बताया कि प्रारंभिक आपत्ति पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है, जिस पर आज तर्क होना था, लेकिन कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने के कारण समिति के सदस्य उपस्थित नहीं थे, इसलिए सुनवाई संभव नहीं हो सकी। समिति अध्यक्ष द्वारा अब अगली सुनवाई 29 जनवरी 2026 को रखी गई है।

30 दिन के भीतर देना है निर्णय-जेपी श्रीवास्तव

सर्व आदिवासी समाज की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता जे.पी. श्रीवास्तव ने कहा कि सत्यापन समिति के अध्यक्ष द्वारा आज सुनवाई की जानी थी, लेकिन कर्मचारियों के अभाव में तारीख बढ़ा दी गई है। हाईकोर्ट द्वारा इस मामले में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जाति प्रमाणपत्र विवाद से जुड़े प्रकरण में शीघ्र निर्णय लिया जाए। आदेश में 30 दिन के भीतर निर्णय देने का उल्लेख है। पीठासीन अधिकारी ने यह भी कहा है कि दोनों पक्ष अपने-अपने तर्क लिखित में प्रस्तुत करें, इसके बाद निर्णय दिया जाएगा।

कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण बढ़ी तिथि

अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि आज की तारीख केवल कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण बढ़ी है। अब 29 जनवरी अगली तारीख तय की गई है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि उस दिन समाज को संतोषजनक निर्णय नहीं मिला, तो इसके बाद उग्र आंदोलन किया जाएगा।

अज्ञात वाहन की ठोकर से घायल की मौत

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। अज्ञात वाहन की ठोकर से घायल युवक की मौत हो गई। पुलिस ने बताया मृतक महेश तिवारी पिता शिवप्रवेश तिवारी कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम केपी का रहने वाला था। 28 दिसम्बर को वह अपने एक साथी को छोड़ने के लिए मोटरसायकल से ग्राम हसुली गया था। वापस आते समय निर्भय पटेल नामक एक व्यक्ति को मोटरसायकल में बैठाकर वापस गांव आ रहा था। रास्ते में अज्ञात वाहन का चालक इन्हें ठोकर मार दिया, जिसमें निर्भय को मामूली चोट आई थी। महेश को आई गंभीर चोटों को देखते हुए नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र से प्राथमिक जांच, उपचार के बाद रिफर करने पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर स्वजन पहुंचे, यहां जांच के बाद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर लिया है।

बस की ठोकर से घायल महिला की मौत

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। बस की ठोकर से घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बसंतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कोटराही की अतवारिया पति स्व. जवाहिर कोइरी 57 वर्ष, रविवार की शाम को सड़क पार कर रही थी, इसी दौरान बैढ़न से अंबिकापुर की ओर आ रही गुप्ता बस का चालक लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए महिला को चपेट में ले लिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। घायल महिला को वाड्रफनगर स्वास्थ्य केन्द्र से प्राथमिक चिकित्सा के बाद रेफर करने पर स्वजन मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर लेकर पहुंचे, यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन के सुपुर्द कर दिया है।

प्रत्येक सोमवार को प्रात: 10.30 बजे से आयोजित होगी समय-सीमा की बैठक

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। जिले में सप्ताह में मंगलवार को आयोजित होने वाली साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक अब आगामी सप्ताह से प्रत्येक सोमवार को प्रात: 10.30 बजे से जिला कलेक्टरेट कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित होगी। इस संबंध में कलेक्टर अजीत वसंत ने सर्व कार्यालय एवं विभाग प्रमुखों को पत्र जारी कर समय सीमा की बैठक में व्यक्तिगत रूप से अनिवार्यत: उपस्थित होने कहा है। उन्होंने निर्देश जारी कर कहा है कि यदि कोई अधिकारी शासकीय कार्य या अन्य कारणों से बैठक में अनुपस्थित रहता है, तो बैठक से एक दिवस पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। अपनी अनुपस्थिति में प्रतिनिधि के रूप में विभाग के ऐसे अधिकारी को बैठक में भेजा जाए, जिसे विभागीय कार्यों के बारे में संपूर्ण जानकारी हो। आदेशानुसार समस्त तहसीलदार एवं मुख्य नगर पंचायत अधिकारी प्रथम एवं तृतीय सोमवार में आयोजित होने वाले समय-सीमा की बैठक में उपस्थित रहेंगे। वहीं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वितीय एवं चतुर्थ सोमवार में आयोजित होने वाले समय-सीमा की बैठक में उपस्थित रहेंगे।

प्राकृतिक आपदा में मृतकों के वारिसों के लिए 24 लाख रुपये स्वीकृत

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। अपर कलेक्टर सरगुजा द्वारा प्राकृतिक आपदा में मृतकों के वारिसों को 24 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है, जिसमें तहसील अंबिकापुर के केशवपुर निवासी ढोलू की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके वारिस बलिन्दर, तहसील अंबिकापुर के घुटरपारा निवासी रोहित जायसवाल की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके वारिस कन्हैया प्रसाद जायसवाल, तहसील दरिमा के टपरकेला निवासी दिव्यांशी बखला की मृत्यु सांप के काटने से होने पर उनके वारिस राम प्रसाद बखला, तहसील दरिमा के परसोड़ीखूर्द निवासी राकेश राव की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके वारिस गोमती राव, तहसील लखनपुर के लखनपुर निवासी ध्वनी की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके वारिस कलावती एवं तहसील लखनपुर के पुहपुटरा निवासी शिवप्रसाद की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके वारिस आगिया बाई को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि की मंजूरी राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 संशोधित प्रावधानों के तहत दी गई है।

शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में दवा खरीदी के मामले में शिकायत पर हुई जांच

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवापारा में दवा खरीदी के मामले में प्राप्त शिकायत पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा 23 अक्टूबर 2025 को 06 सदस्य जांच समिति का गठन किया है। जांच समिति के द्वारा मामले की जांच कर, जांच प्रतिवेदन 19 नवंबर 2025 को प्रस्तुत किया गया था। जांच प्रतिवेदन अविलम्ब 25 नवंबर 2025 को संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं सरगुजा कार्यालय को प्रेषित किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि 01 दिसंबर 2025 संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं सरगुजा द्वारा प्रेषित पत्र में वित्तीय वर्ष 2024-25 में क्रय समिति के प्रभारी कर्मचारी/अधिकारी का नाम व पदनाम के सबंध में जानकारी चाही गई है, जिसे संबंधित कार्यालय को प्रेषित करके जानकारी की मांग की गई है।

कीटनाशक का सेवन किए वृद्ध की मौत

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। शराब के नशे में वृद्ध कीटनाशक का सेवन कर लिया, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बलरामपुर जिला के बसंतपुर थाना अंतर्गत ग्राम कोलुवा निवासी रामनारायण पिता स्व. शीतल गोड़ 65 वर्ष, 22 दिसम्बर को गांव के सोसायटी से चावल लेकर घर आया और शराब पीने के बाद पूरी रात अपने परिवार के सदस्यों के साथ गालीगलौज कर रहा था। सुबह स्वजन उसे उल्टी करते देखे, तो पता चला कि वह कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया है। स्वजन उसे वाड्रफनगर स्वास्थ्य केन्द्र ले गए, यहां से प्राथमिक चिकित्सा के बाद रेफर करने पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर लेकर पहुंचे, यहां इलाज के दौरान रविवार की शाम को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन के सुपुर्द कर दिया है।

कैलेण्डर वर्ष 2026 हेतु स्थानीय अवकाश घोषित

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। कलेक्टर अजीत वसंत के द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक-04 के नियम-8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के लिए कैलेण्डर वर्ष 2026 हेतु स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। जारी आदेशानुसार, ढोल ग्यारस (करमा) 22 सितंबर 2026, दशहरा (महा अष्टमी) 19 अक्टूबर 2026 तथा दीपावली का दूसरा दिन (गोवर्धन पूजा) 09 नवंबर 2026 को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। कोषगारों, उप कोषगारों के लिए यह अवकाश नहीं होगा।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक- मनीष पाठक द्वारा स्पीड प्रिंटर्स व आफसेट पुराना पोस्ट ऑफीस रोड दर्रीपारा अम्बिकापुर पिन नं. 497001 (छत्तीसगढ़) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-रणविजय सिंह तोमर